the basis of figures shown on the machine plus vote recorded through Tellers, I.. announced yesterday that

Ayes had—336

and Noes—155

After checking with the photograph it has since been found that the correct figures are:

Ayes—331

Noes—154

In any case, the result of the division as announced by me is not materially affected. here is clear two-thirds majority. The motion was duly carried.

I also put it down on the notice Board.

An Hon. Member: There were five duplicate votes. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: his is after due checking. I again tell you, this is the figure given by the Office after due checking.

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने मान लिया है कि पांच डुप्लीकेट बोट कास्ट हुए हैं । लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा । कौन-कौन मैम्बर हैं ?

MR. SPEAKER: After you took the objections, there was rechecking, and this is the rechecked thing; and I declared the Bill duly passed after rechecking. (*Interruptions*). It came on the board, everything is there on the record, there is no doubt about it.

(श्री कुवर लाल गुप्त): पांच ने डुप्लीकेट वोट किया, यह आपने मान लिया । उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): On a point of order.

MR. SPEAKER: No Points of Order now. I am not prepared. Let me proceed. It is all right. If you want to examine it, it is all right. (*Interruptions*).

Please proceed now.

MR. KANWAR LAL GUPTA.

15.08 hrs.

MOTION RE: INDIAN TERRITORY BEING SHOWN AS PART OF CHINA IN RUSSIAN ENCYCLOPAEDIA

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इसी विश्वकोष में भारत के बहुत बड़े राज्य क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाए जाने पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार को विरोध पत्र न भेजने की सरकार की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय भारत की 55,000 वर्गमील भूमि रूसी नक्शों में चीन का भाग दिखाई गई है । यह बहुत गम्भीर बात है । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह सारे देश के स्वाभिमान और मर्यादा का सवाल है । इस प्रकार से जो कार्रवाई रूस ने भारत के विरुद्ध की है, यह काटेग्राफिक एग्रेशन का क्लीयर केस है, उसके अलावा कुछ नहीं । जब मंत्री महोदय से पूछा गया कि रूस ने भारत सरकार के प्रोटेस्ट का क्या जबाव दिया, तो उन्होंने राज्य सभा में कहा कि रूस ने कहा है कि इन नक्शों की कोई पोलीटिकल सिग्नीफिकेंस नहीं है, हमारे स्पैशलिस्ट्स ने इस सवाल को टेकनिकल तरीके से डील विद किया है और हम हिन्दुस्तान की टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन का सम्मान करते हैं । अगर किसी ऐटलस या नक्शे में एक बार गलती हो जाये, तो मैं उस को मान सकता हूं । हर जगह गलती हो सकती है । लेकिन यह मामला कोई एक या दो साल का नहीं है । यह मामला 1955 से चला आ रहा है और इस को चलते हुए सोलह साल हो गये हैं । हमारी सरकार बार-बार रूस को कहती है, लेकिन उस के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकलता है ।

सबसे पहले यह मामला 22 अगस्त 1960 को पार्लियामेंट में उठाया गया । प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी, श्री सादत अली खां ने जवाब दिया कि हम ने यह सवाल रूस सरकार से उठाया है और रूस सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे । उन्होंने यह माना कि रूस सरकार के नक्शों में 1955 से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा चीन का हिस्सा दिखाया गया है । पिछले सोलह सालों में रूस ने पांच ऐटलस और नक्शे छापे हैं और करोड़ों नक्शे छापे गये हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि उन करोड़ों नक्शों में क्या एक भी नक्शा ऐसा छापा गया है, जिस में भारत की भूमि को ठीक दिखाया गया हो ?

अभी रूस की क्रान्ति की पचासवीं एनिवर्सरी के अवसर पर 1969 में एक नई ऐटलस छापी गई । वह ऐटलस सरकारी तौर पर, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार की मुहर से छापी गई । उस ऐटलस के प्रिफेस में से मैं कुछ क्वोट करना चाहता हूं :

The Preface reads:

"The curent Third Edition of the Great Soviet Encyclopaedia is published in conformance with the decree of the Central Committee of the Communist party of the Soviet Union and the Council of Ministers of the Union of Soviet Socialist Republics.

..The scinific programme of the Encyclopaedia was defind by the decree of the Central Committee of the Soviet Union".

इस का मतलब साफ़ है कि सरकारी बैंकिंग और सरकारी मुहर के साथ यह एनसाइक्लोपीडिया छापी गई । शायद मंत्री महोदय के गले में रूस का यह स्पष्टीकरण उतर जाये कि इस की कोई पोलीटिकल सिग्नीफ़िकेंस नहीं है । लेकिन किसी भी समझदार व्यक्ति के गले में, जिस को थोड़ी भी अक्ल है, यह बात उतरने वाली नहीं है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि रूस हमारा दोस्त है और उस के बारे में एक दूसरे ढंग से सोचना चाहिए और उस की इनटेंशन को देखना चाहिए । मैं मान सकता हूं कि दोस्त एक बार ग़लती कर सकता है । लेकिन सोलह साल तक लगातार याद दिलाने के बावजूद वह दोस्त गलती करता जाये और नक्शों को ठीक न करे, यह एक अनप्रैराल्ड इन्सिडेंट है, जिस की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है ।

चाइनीज़ ने भी ऐसा ही किया था । जब जवाहरलाल जी चीन में गये थे, तो उन्होंने चीन के गलत नक्शों के बारे में चाउ-एन-लाई से प्रोटेस्ट किया था । चाऊ-एन-लाई ने कहा कि ये नक्शे पुराने छपे हुए हैं, हम इन को ठीक कर देंगे । लेकिन बाद में चीन ने उन नक्शों को कैसे ठीक किया ? 1962 में चीनी सेना हिन्दुस्तान की धरती पर आ गई, और जो कुछ हुआ, मुझे उस के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । जो कुछ रूस कर रहा है, उस का भी पैटर्न वही है, जो कि चीन का था । मेरा कहना यह है कि जो कुछ रूस ने किया है, वह एक डेलिबरेट, प्री-प्लान्ड और मिसचीवस मूव है । यह एक गम्भीर मूव है । जिस देश को भारत की पचास करोड़ जनता की भावनाओं की कद्र नहीं है, जिस को भारत की भूमि चीन का भाग दिखाने में शर्म नहीं है, जो भारत सकी सरकार की चिन्ता नहीं करता है, उस का यह कहना कि इस की पोलीटिकल सिग्नीफिकेंस नहीं है, बेवकूफी की निशानी हो सकती है, और कुछ नहीं ।

सोवियत यूनियन के अलावा, जो कि कई लोगों का फ़ादरलैंड है, हंगरी में, ईस्ट जर्मनी में, जिस के डिप्लोमेटिक मिशन का दर्जा अभी बढ़ा दिया गया है, और दूसरे

दिया गया है, और दूसरे ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज में भी इसी तरह के नक्शे छापे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि भूतपूर्व स्पीकर, श्री अनन्तशयनम् अयंगर, ने 9 अप्रैल, 1961 को सरकार के मंत्री को कहा था कि इस प्रकार के सभी नक्शों की जांच कर के रिपोर्ट दी जाये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्पीकर की उस डायरेक्शन का पालन किया गया। क्या सरकार को यह मालूम है कि ईस्ट यूरोपियन कन्ट्रीज के कितने नक्शों में भारत की धरती को चीन का भाग दिखाया गया है? मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि अमरीका और इंग्लैंड के कुछ नक्शों में भी भारत धरती को चीन या पाकिस्तान की धरती दिखाया गया है। वे देश भी उतने ही दोषी हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, न हम चीन के एजेंट हैं, और न इस के दलाल और न अमरीका और इंगलैंड के दलाल। हमारे दिल में भारत माता, और केवल भारत माता का दर्द है, हो सकता है कि कुछ भाइयों को रूस का दर्द हो और दूसरों को अमरीका और इंग्लैंड का दर्द हो।

सवाल यह है कि आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इस के पीछे उस का क्या परपज है।

मेरा कहना यह है कि परपज इस का साफ है। यह चाहता है कि रूस और चीन का जो झगड़ा है भारत की कीमत के ऊपर वह झगड़ा सुलझाया जाय। वह भारत की धरती का गिफ्ट देकर के अपना जो झगड़ा है उस को सुलझाना चाहता है। जब यह नक्शे बने थे 1956 में उस समय तो चीन और रूस हनीमून कर रहे थे। आज थोड़ा सा झगड़ा है: लेकिन वह चीन को ऐनौम करना नही चाहता। स्तान की सरकार को टेकेन फार ग्रान्टड ता है कि यह सरकार क्या है, बोलते हैं लयामेंट में मंत्री, आधी दबी जबान से, ल कर के चुप हो जाएंग। और कोई मतलब है नहीं, इसलिये इस सरकार की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

मेरा सवाल मंत्री महोदय से दूसरा है। अगर कल को दुनिया की अदालत में यह सवाल गया, आप बार-बार कहते हैं कि रूस हमारा मित्र है, मैं भी रूस के साथ मित्रता चाहता हूं, मेरी पार्टी रूस के साथ मित्रता चाहती है हर एक देश के साथ चाहती है वह चाहे डिक्टेटरशिप हो या डमोक्रसी हो, कोई कंट्री हो, हर एक के साथ हम मित्रता चाहते हैं लेकिन बराबरी की हैसियत से, सम्मान रख कर, इज्जत रख कर, तो मैं यह पूछता हूं कि अगर कल को दुनिया की अदालत में यह मामला गया और लोगों ने कहा कि यह देखिए, रूस जो भारत का मित्र है, उस की एटलस में यह नक्शे हैं तो उस का क्या गंभीर परिणाम उस पर पड़ सकता है यह आप ने सोचा है? हम ने दुनिया की अदालत में कई बड़े-बड़े केस खोये हैं। अपने देश की धरती खोई है इस सरकार की बवकूफी की वजह से। तो आप सोलह साल तक क्यों सोते रहे? क्या इसी प्रकार के से 50 हजार वर्गमील का भूमिदान देने का इरादा है? क्या यह बात आप ने सोची है? अगर यह कहा जाता है कि यह तो किसी टकनीशियन ने यह चीज बना दी, तो आप को मालूम है कि सोवियत यूनियन तो एक क्लोज्ड सोसायटी है। कोई डमोक्रसी तो वहां है नहीं और वहां पर जहां इतना रेजिमेंटशन है, वहां तो बीबी और पति के संबंध में भी स्टेट का दखल है, यह नक्शे की बात तो छोड़ दीजिए ..... **(व्यवधान)**

15.23 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से जो क्लोज्ड सोसाइटी है जहां सरकार की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता हो वहां पर यह बात कहीं जाये कि सरकार की बगैर मर्जी के इस प्रकार से नक्शे बनाए जा रहे हैं

[श्री कंवर लाल गुप्त]

16 साल तक यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इतना ही नहीं, रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस है, या मास्को रेडियो है, हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं को जिसने गालियां दीं, महात्मा गांधी तक के खिलाफ आवाज उठाई और देश की जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश की... (**व्यवधान**)... उपाध्यक्ष महोदय, आप इन को रोकिए मत । इन को तकलीफ होना स्वाभाविक है । जब दलाली लेते हैं तो तकलीफ तो होगी ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सोवियट रूस ने जो हमारे देश की मदद की वह भी तो कहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, मेरे मित्र कह रहे थे कि रूस ने बहुत मदद की । मैं भी मानता हूं कि रूस ने हमारी काफी मदद की । रूस ने हमारी मदद काश्मीर में भी की । मैं मानता हूं । कोई इनकार नहीं कर सकता । लेकिन उस मदद का यह मतलब समझा जाए कि 16 साल तक हमारे देश की 50 हजार वर्गमील भूमि चीन की भूमि करके दिखाए? इस बात की इजाजत हम उसे नहीं दे सकते । यह बात समझ लेनी चाहिए ।

मैं रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस की बात कर रहा था । जब हमने यह बात उठाई तो सरकार की तरफ से कहा गया वह तो इण्डिपेंडेंट है, सरकार के अधीन नहीं है । क्या वहां कोई चीज इण्डिपेंडेंट है ? और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो अखबार वहां से आ कर सर्कुलेट होते थे सब के बीच में, कोई भी ले सकता था वह सर्कुलेशन बन्द कर दिया । इस प्रकार की बातें करके जो पाप है इस सरकार के उसको दबाने की जान बूझ कर साजिश की जा रही है ।... (**व्यवधान**)... अब इस गवर्नमेंट का क्या रोल है ? यह सरकार एक कमजोर और धीमी आवाज के साथ प्रोटेस्ट करती है । उसका असर भी उतना ही धीमा होता है । इस सरकार में जो कुछ करने का एक विल पावर होना चाहिए वह नहीं है, यह मेरा चार्ज है इस सरकार पर । सरकार ने कहा कि हमने चार प्रोटेस्ट नोट भेजे हैं मैंने अखबार में पढ़ा कि वह लाइब्रेरी में रखे हैं । मैं आज तीन घण्टे लाइब्रेरी को ढूंढ़ता रहा । मुझ को तो वह प्रोटेस्ट नोट मिले नहीं । मेरा कहना है कि वह प्रोटेस्ट नोट नहीं थे । वह जो बातचीत इन की हुई थी उसको लिख करके वहां पर भेजा गया था । बस । वह प्रोटेस्ट नोट नहीं थे । ए सार्ट आफ डी-मेमोटायर या ऐसा कुछ कहते हैं उसे । इस लिए मैं पहली मांग तो यह करूंगा कि जो प्रोटेस्ट नोट आपने भेजे हैं और 16 साल में उसके ऊपर रूस का जो जवाब लिख कर आया क्या उसे आप सभा के पटल पर रखेंगे ? अगर नहीं रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि यह दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं । कुछ चीज आप दिखाना चाहते हैं, कुछ छिपाना चाहते हैं । मैं आप के जरिए मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह जितनी चीजें हैं उसे सामने लाएं कि आपने क्या किया और रूस ने क्या किया ? उसका दृष्टिकोण क्या है यह भी हम समझते हैं । मैंने कहा कि यह कोई पार्टी की बात नहीं है । मैं शशिभूषण जी से भी कहूंगा कि यह कांग्रेस जनसंघ का सवाल नहीं है, यह सारे देश के सम्मान का सवाल है । आप पार्टी के सवाल को उठा कर इस सवाल को पीछे मत डालिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा डिप्लोमेटिक मिशन जो मास्को में है, उन्होंने यह एटलस छापने की बात नहीं बताई कि यह एटलस छापा है और इस में हमारा इतना हिस्सा अपने देश का दूसरे देश का हिस्सा दिखाया गया है । यह हमारे डिप्लोमेटिक मिशन्स करते क्या हैं ? यह केवल टोस्ट प्रोपोज करते रहते हैं शराब के अन्दर और पार्टीज के अन्दर और इम्पोर्टेड

आर्टिकिल्स सस्ते किस तरह से इकट्ठे किए जा सकते हैं यह देखते रहते हैं । बाकी इनके अलावा तीसरा और कोई काम यह नहीं करते । केवल यह दो ही काम यह करते हैं । नहीं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीन तीन महीने एटलस को छपे हुए हो गए लेकिन उन्होंने आप को इस की खबर तक नहीं दी, यह आप ने खुद स्वीकार किया है कि हमने रिपोर्ट मांगी है । मेरा कहना यह है कि यह इस सरकार की डिप्लोमेसी की जबर्दस्त फैल्योर है । अभी कुछ दिन पहले मन्त्री महोदय ने बड़ी बहादुरी के तरीके से कहा कि हमने सारे ऐसे नक्शे बैन कर दिए हैं । मैं पूछूं कि कितने नक्शे आए जब से आप ने बैन किया ? और कितने आपने उसमें पकड़ लिए ? उनकी संख्या कितनी है ? कितने रूसी एटलस यहां पर आते हैं ? शायद दो चार दस लाइब्रेरी में आते हों तो आते हों । मैं उसको बुरा नहीं कहता । मैं समझता हूं कि आपने ठीक किया । लेकिन क्या इतना करना काफी है ? कितने आते हैं ? कुल कोई दस पन्द्रह । लेकिन इतना कह कर सन्तोष करना गलत है । सवाल यह है कि रूस अपने नक्शे को बदलने के लिए तैयार है या नहीं ? क्या रूस अपने नक्शे में तरमीम कराने के लिए तैयार है या नहीं ? अगर नहीं तो रूस को किस तरह से बाध्य कर रहे हैं यह एक सवाल है जो मैं आप से पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां हमारे जो राजदूत हैं, वे कहते हैं कि वे वहां के डिप्टी मिनिस्टर से मिले थे, उन से बातचीत की थी । उसके बाद वे यहां आये और प्रधान मन्त्री से भी मिले थे, शायद आप के दर्शन भी उन्होंने किये होंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में रूस सरकार का क्या जवाब है ? रूस सरकार पिछले 16 साल से इस तरह की शरारत क्यों कर रही है ? इसके बारे में आप के राजदूत ने क्या बताया, आप उस पर रोशनी डालिये ।

दूसरा सवाल—अगर रूस 16 साल के लगातार परिश्रम करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आप रिटेलिएट क्यों नहीं करते? बी० बी० सी० ने हमारे देश की गलत तस्वीर छाप कर हमारे देश के नाम पर बट्टा लगाया, आप ने बी० बी० सी० के रिप्रेजेन्टेटिव को निकाल दिया, हमारी पार्टी ने और हमने उसका स्वागत किया, लेकिन क्या आप डबल-स्टैण्डर्ड रखना चाहते हैं ? अगर बी० बी० सी० के रिप्रेजेन्टेटिव को निकाला जा सकता है तो क्या रूस के साथ ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता ? आपने कहा कि उस कारस्पोंडेंट का कोई कुसूर नहीं था, लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं था, बी० बी० सी० के खिलाफ गुस्सा दिखलाने का । अगर गुस्सा दिखाने के लिये बी० बी० सी० के कारस्पांडेंट को निकालना जरूरी था तो आपका गुस्सा 16 साल तक रूस के मामले में कहां गया, सरदार जी ? क्या रूस के मामले में सरकार को गुस्सा नहीं आता है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर आता है, तो मैं मांग करता हूं कि जैसे आप ने बी० बी० सी० के कारस्पौंडन्ट को निकाला है, उसी तरह से आप रूस के कल्चरल एटेची को निकाल दीजिये । मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन्ज तोड़ने के हक में नही हूं, लेकिन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिये । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने कहा है कि बी० बी० सी० के कारस्पोन्डट को जो निकाला गया है, वह कुछ ज्यादती की गई है. . .

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आप की क्या राय है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं तो इस मामले में आप का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह चार्ज जरूर लगाता हूं कि आप की जो तराजू है, वह रूस के लिए अलग और अमरीका और इंग्लेंड के लिए अलग है. . .

श्री रा० कृ० सिन्हा (फैजाबाद) : यही आप की भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आप ने भी मान लिया कि आप की भी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : त्रिवेन्द्रम के अन्दर जब रूसी दूतावास ने अपना एक कल्चरल सेन्टर बिना आज्ञा के बनाया आप को उसे रोकना चाहिये था, लेकिन आप ने यह कह दिया कि जितने दूसरे दूतावास इस तरह से बगैर आज्ञा के बना रहे है, वे उस को बन्द कर दें, लेकिन हम ने उस का भी स्वागत किया। दिक्कत यह है कि जब रूस का सवाल आता है, तब आप दूसरो को भी लपेट लेते हैं—हम तो इन सब के खिलाफ है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नही आती कि रूस के बारे में एक्शन लेने में आप की भुजायें ढीली क्यों पड़ जाती हैं, आप को पसीना क्यो आ जाता है। इस का, उपाध्यक्ष महोदय, कारण है—आप की इस के बारे में कोई यूनीफार्म पालिसी, नहीं है और मेरा अनुरोध है कि सरकार को अपनी एक यूनीफार्म पालिसी बनानी चाहिये। हम मित्रता चाहते है, मेरे एक मित्र ने कहा कि वह हमारे दोस्त हैं, मैं मानता हूं कि वे हमारे दोस्त हैं, सब लोग हमारे दोस्त हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्त को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि हमारे देश की भूमि दूसरों को भी दे दे। डिप्लोमेसी में हर एक देश दोस्त है, लेकिन हर एक देश दुश्मन भी होता है, क्योंकि हर एक देश जब उस का नेशनल इन्टरेस्ट यह डिमाण्ड करता है कि दूसरे देश को दबाया जाये, तो वह वैसा करता ही है। इसलिये आप को सतर्क रहने की जरूरत है—चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। लेकिन यह सरकार सोती रहती है, इस की कोई यूनीफार्म पालिसी नहीं है, अगर डिप्लोमेसी में इस का कोई रिकार्ड है तो वह बंगलिंग्ज और ब्लण्डर्ज का रिकार्ड है, इस के अलावा कुछ नहीं है . . .

श्री स्वर्ण सिंह : चार-पांच दफ़ा आप इस को रिपीट कर चुके हैं, अब खतम कीजिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर आप 16 साल तक प्रोटस्ट नोट भी नही भेजते, तो आप किस प्रकार के मंत्री हैं, यह कैसी सरकार है?

उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था इस का कारण क्या है कि इन की भुजायें रूस के सामने ढीली क्यों हो जाती हैं। इस का मुख्य कारण यह कि इन की डिपेण्डेन्स रूस के ऊपर इतनी ज्यादा हो गई है कि ये उसके सामने आंख मिला कर खड़े नहीं हो सकते और आज देश को जिस ढ़ग से ये ले जा रहे हैं, रूस का एक सैटेलाइट-टाउन बनाने की कोशश कर रहे हैं, इतना ही नहीं, यहां की कम्यूनिस्ट पार्टी की मदद से चूंकि यहा की सरकार जिन्दा है, इस लिए ये रूस की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकते। यही कारण है कि आज देश के औनर, देश के सम्मान की इन को चिन्ता नहीं है, अपनी कुर्सी बनाये रखने के लिये चूंकि इन को कम्यूनिस्टों की मदद की जरूरत है, इस लिए ये आंखें बन्द किये हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन जब शोर होता है तो कुछ थोड़ी सी बात कह देते हैं,

श्री स० मो० बनर्जी : पहले मेरा प्रस्ताव पढ़ लीजिये, तब बोलिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : कल ही प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ हिस्ट्री बनाई है, एक-डेढ़ साल पहले आप की हिस्ट्री कहां थी। अब कहते हैं कि हम ने कल सदन में जो डिसीज़न लिया, वह हिस्टोरीकल डिसीज़न था। वह हिस्ट्री हो या न हो लेकिन जब फाइनेन्स बजट आया था, तब भी हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह हिस्टोरीकल बजट है, इस में केवल 4 परसेन्ट प्राइस इन्क्रीज़ होगा,

लेकिन 7 महीने के बाद 15 से 25 परसेन्ट तक एसेन्शल कमाडिटीज की प्रइसैज बढ़ गई हैं...

श्री स्वर्ण सिंह : बनियों की महरबानी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : कुछ अकल सीखो, कोई और जवाब नहीं है। इतने कम्यूनल नेचर के आदमी हैं, 24 घन्टे बनिये-बनिये...

श्री स्वर्ण सिंह : "बनिये" कम्यूनल नहीं हैं, कोई अपमान की बात नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : कुछ शिष्टाचार सीखो...

श्री स्वर्ण सिंह : सभी कौम में बनिये हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, कम्यूनल नेचर की बात एक्सपंज कर दी जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं कह रहा था कि इन की हिस्ट्री को देखा जाय--इन की जेब अपमानों से भरी हुई है, मैं उस लम्बी-चौडी गाथा को कहां तक सुनाऊं, चाहे रब्बात का मामला हो, चाहे चीन ने लात मार कर इन की हजारों मील जमीन को हथिया लिया हो, चाहे पाकिस्तान ने काश्मीर के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया हो, क्या यही इतिहास है जिस को दिखलाना चाहते हो?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर रूसी सरकार कुछ नहीं करती तो आप उन से कहिये कि यह अनफ्रेण्डली एक्ट है, इस को दोस्ती का रिश्ता नहीं कह सकते इस को दोस्ती का सुबूत नहीं कह सकते और अगर आप इस प्रकार से उनको लिबर्टी देते जाएंगे तो यह लिबर्टी केवल नक्शों तक ही सीमित नहीं रहेगी, कल आप पर एग्रेशन भी हो सकता है। इस को रोकने के लिये जब शुरूआत होती है, उसी वक्त कदम उठाने की जरूरत होती है। इस लिये मेरी मांग है कि रूस के नक्शों को ठीक कराने के लिये सख्त कदम उठाने चाहियें, उन की तरफ से ठीक करिजेण्डा प्रकाशित होना चाहिये और जैसा मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार की जितनी कौरस्पौंडेंस है, जितने प्रोटेस्ट नोट हैं, वे सदन के सामने रखे जायें। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, मैं अपने दोस्त बनर्जी साहब से प्रार्थना करूंगा, चाहे मैंने उन के फादरलैन्ड का जिक्र किया है और चाहे आप इस के विरोध में हों, लेकिन आप ने इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती का पानी पिया है, क्या मैं आप से आशा करूं कि आप मेरे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे कर इस भूमि की इज्जत को रखेंगे..

श्री स० मो० बनर्जी : आप का फादरलैंड ताइवान है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा फादरलैंड केवल हिन्दुस्तान है, आप का फादरलैंड कुछ और हो सकता है। मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव के हक में वोट दे कर सरकार पर पूरा जोर डालें कि सरकार उस एग्रेशन के खिलाफ जो रूसी नक्शों में भारत की भूमि को चीन की भूमि दिखलाया गया है, शीघ्र कारवाई करे। अगर सरकार दो-तीन महीनों के अन्दर कार्यवाही नहीं करती, तो देश के अन्दर एक जबरदस्त एजिटेशन होगा और वह किसी पार्टी की तरफ़ से नहीं सारे देश की तरफ़ से होगा। और उसके अन्दर मैं आशा करता हूं कि मेरे साथी जो सामने बैठे हैं वह अपना सहयोग देंगे कि यह सरकार या तो ठीक करे नहीं तो सरकार को बाध्य कर दिया जाये कि वह यहां से हट जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to U.S.S.R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encyclopaedia."

There are two amendments.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): I beg to move:

That in the motion,—

(i) *after* "sending" *insert*—

"in time"

(ii) *add* at the end—

"and in not pursuing the matter to any logical conclusion" (1)

SHRI S. M. BANERJEE: I beg to move:

That in the motion,—

for "disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to U.S.S.R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encyclopaedia".

Substitute—

"in view of the Government of India's action to ban those U.S.S.R. maps which show large chunks of Indian territory as part of China, recommends to the Government to ban or suitably black out all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan" (2)

SHRI SANT BUX SINGH (Fatehpur): Sir, I think everybody in this country has felt anxious about the publication and the continuance of wrong boundaries in Soviet maps. This is not a partisan issue and it should not be made into one. Whenever such an effort is made, people who feel that they are furthering the cause of the country are merely fulfilling the cause of their own parties. No party is bigger than the country. We all join in pointing out to the Soviet Union that it is a sad state of affairs that this publication has continued for the last 15 years. However, beyond this point, I find it difficult to agree with almost anything that Mr. Kanwar Lal Gupta said.

Let us start with his most important suggestion about the action to be taken. He suggested that this Government ask the Russian Cultural Attache to be sent away. Need I tell him that such maps have been published not only by the Soviet Union but by most East European countries? We will have to send away the Cultural Attaches of all those countries. Not only that. There are worse maps. There is a map in the American Encyclopaedia which shows Kashmir as an independent State. There is a map of the UN and American maps which do not show Goa as a part of India. There are also British maps and Swiss maps. Is he suggesting that we break relations with all these countries because maps of this kind are published? Is this country going to be dependent for its national integrity and safety of its territory on maps printed at other places? If the Government took action in sending the BBC Correspondent away, the Government has also taken action in banning all publications, no matter from which country they happen to come, that show wrong boundaries.

Sir, when we make remarks of the kind that Mr. Kanwar Lal Gupta made about our diplomats, we are misusing our office and bringing down our diplomats in the eyes of people elsewhere. May be it would be possible for them to say, had they the immunity, that "If some Members of Parliament merely see us drinking, it is because they happen to come to us only at the time when we are drinking and they never come when we are working or any other time." Therefore, I would

suggest that this kind of remark should not be made.

Now Shri Gupta says in his motion that there has been no written protest and the Government is to be censured because there is not a written protest. On the other hand, Shri Gupta himself admits that he has seen four of these . . . . (*Interruption*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I have not seen.

SHRI SANT BUX SINGH: Of course, he has made a distinction. I am coming to that. Shri Gupta says that these notes are aide memoirs. What are aide memoirs? Every time maps of this kind have been published we have immediately taken them up with the Soviet Government. We have had conversation with them and these have been followed by a full summary, a full transcription, of the talk we have had, of the protest we have lodged.

Must our protest be abusive? Is this the way of Indian diplomacy? Is it the language that is being obejcted to? Must we speak internationally in the same language, in the same tone, in the same manner as we have spoken in this House since this morning? I am sure, nobody would feel inclined to do anything of the kind.

It has been said that there is political significance to the publications of such maps. Let me take Shri Gupta's mind back to the fact that these maps were published in 1955 but in 1962 and 1965 when we were fighting, on both occasions we were fighting with Russian arms. Is this not politically significant? On either of these occasions the Soviet Union could have come out on the side of China. If I am making a wrong statement, I would like to quote the remarks of Mr. Dean Rusk, Secretary of State of the United States of America, made to me personally. These remarks were that in 1965 when Pakistan aggressed against India and China threatened to come in, "We and the Russians, both, made it clear to the Chinese that they should not interfere."

As far as political action is concerned, these maps have had no bearing. This country is not going to be moved or agitated by measures as small as this. As the Foreign Minister has said on several occasions, if maps are going to agitate us, any country in the world can choose and move a line a little from here to there and our Foreign Minister and Foreign Office will go round begging for the correction of these maps and whenever these lines are corrected our Foreign Minister and, through him, our country will feel obliged.

Territories of this country have to be defended by the citizens of this country, by the arms and the might of this country. Territories are not dependent on the mercy either of the United States or of the Soviet Union. We have amply made it clear to both these countries. When they pressurised us, that is, two of the superior superpowers, the Russians and the Americans, about signing the nuclear treaty, India, despite all her difficulties, refused to sign that treaty. No country could have faced greater pressure than the pressure that was brought on us on this occasion.

Last of all I would like to put it to this House that foreign affairs is a national concern. The honour of this country is the concern of every citizen, of every Member of Parliament. But what I have seen in the last three years in this House is that whenever there is some situation, something occurring in some distant place, we do not stand up and talk sober. We do not stand up and voice the feeling of the people of this country. But we make these issues into issues of narrow partisan political interests.

Foreign policy should not be the subject of sentiment. Foreign policy should be the subject of hard realistic thinking, of long-term measures. I wait

[Shri Sant Bux Singh]

for the day when more people from the other side will think of foreign policy not as a matter of a simple broadcast, not as a film, not as a map, but as an effort through which the future and the frontier of this country is safe.

I would request again that, after the first speaker, all the other speakers should kindly bear this in mind and not make some technocrats, some printers, in the Soviet Union feel so important that this great Parliament of India feels agitated. It is not a nice thing that our friends in the Soviet Union should have chosen to allow this map to continue. This is understandable to me. India's friendship is of tremendous value to the Soviet Union. The Soviet Union has far more serious border disputes with China. If publishing such maps could have pleased China, their feuds should have ended.

We should avoid looking at things in terms of either being pro-American or pro-Russian because that is not the international style today. Many of us will realise that the two super-powers have got so close to each other that when it comes to this sub-continent, on most occasions, the Americans and the Russians think alike. We can differ on ideology; we can have our own view-point politically. But Americanism or Russianism in terms of foreign policy is meaningless and is redundant.

So, let us criticise whatever maps happen to be incorrect. But let us not go abegging for maps to be corrected. It is not a very good sight to see the Members of Parliament parading with placards before Embassies. If this country will be defended, it will not be defended by sending our demonstrations to the Embassies. We are a sovereign country; we are an independent country. We can take care of ourselves.

In the end, I would say that I join in the protest at the continuation of the publication of these maps. And I do beseech everyone not to make this an issue on which you attack just one particular country.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as the mover of the motion has pointed out, this is a very serious matter on which this country should be very much concerned. When we express our concern, it is not to undermine the other developments which are taking place in the world. Whosoever insults this country or defames this country or does something which is not friendly to this country, we will, certainly, be one to express resentment and concern about it.

The other day, when the B.B.C. matter came up in the House, I think, the consensus of opinion in the House was that what the Government has done is quite proper and right. I myself, speaking on the Call Attention notice which was in my name and others, started by commending the Government on their taking right and proper action.

It is a fact that matter which has caused deep concern to this country is for two reasons. One is that this country has brought this matter to the attention of the Soviet Union a number of times and the Soviet Union has summarily dismissed it by showing a very cavaliar attitude. I would like to remind the hon. Minister and also the Soviet Government that, when the Soviet Union had confrontation with China on a river and the border dispute, when actually the Soviet army and the Chinese army were in confrontation, we had expressed our opinion. Though it was not a matter of concern directly to us, as a nation which always believes in the objectivity of an issue, and expresses its concern over things that happen in the world which break peace and which bring a feeling of confrontation between one nation and another nation, I remember, we expressed our opinion. In the Consultative Committee also, when we took up this matter, we ourselves said that let the Government of India not play politics There should be no

opportunism in this matter. Let the Government of India go into the entire question. If the Goernment of India feels that the Chinese aggression on Russian border is not fair and that it is not just, let the Government of India express its categorical opinion that this is an unfair act on the part of China. It has nothing to do with us. It has nothing to do with our relationship with the Soviet Union or China. But as a nation which has a certain sense of propriety, we should express a categorical opinion on it.

I remember, in those days, when the Soviet representatives met us, they were coming with a lot of Amul butter to praise our objectivity and to praise our concern for the right thing. I say, in a matter of such deep concern to this country, this Government should not have played politics. This House should not take a partisan attitude. This is a matter concerning this county and the Soviet Union has maintained a particular stand by showing complete indifference to the situation and also making a plea that the Soviet Union does not bother about it because I feel that this map is a different map. Whatever maps that are brought out by private publishers or others may be, this map is not that. I may quote the words of the editor of the encyclopaedia who is a Russian. It is a prestigious publication of the Soviet Union and he writes in his Foreward that this encyclopaedia is being prepared under the decree of the Soviet Government and also the Communist Party of the Soviet Socialist Republic. The Soviet Government directly decree. You all understand 'decree', a word which is used in a particular significance and a particular context. You know 'decree' is not an ordinary word. It is used with a complete sense of authority and a sense of responsibility. What we are concerned is these words that this is being decreed by the authority—mind the word—of the Soviet Socialist Government and also the Communist Party of the Soviet Union. Therefore, this is a matter which has a lot of implications. Behind that there is a purpose and a particular design behind it. It is not a matter of cavalier indifference. I can understand the Soviet Union being cavalier and trying to make it appear as a matter of cavalier and casual interest. I am asking: what is this Government doing? Is it not known to the Government of India that the concern of the Soviet Union in Asia is growing because of its relationship with China? In spite of their efforts their relationship with China has not improved and that is one reason.

We are happy that there is now less tension in Europe as they have come to some terms with West Germany. But, till the other day, I was told and in all the publications and reports coming from the Soviet Union one point which went against Czechoslovakia and Czechoslovakian movement for liberation was this. Sir, you at that time made one point about that. You yourself said that this is one of the reasons why the Soviet Union has brought its tanks into Czechoslovakia so that German infiltration may not tarnish the philosophy of Communism and that is why they did it. It was an application of the Brezhnev doctrine of limited sovereignty to Czechoslovakia to stop Czechoslovakia from German infiltration and German confrontation. I am glad that the Soviet Union has changed that position and today the Soviet Union has come to some agreement with West Germany thus reducing the area of tension in Europe. We are happy about it. What is the purpose? (*Interruptions*) The purpose is this that all that disengagement will culminate into a very very intensive engagement in Asian hemisphere. And the relationship of the Soviet Union with China is going to be a relationship which is going to affect all contries round about Soviet borders and round about Chinese borders and round about Indian borders and that is why we see that in spite of our protest the Soviet Union is continuously supplying arms to Pakistan. So

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

the entire area which is surrounding China, which is surrounding India should be armed and should be made a force from which probably the Soviet Union can get benefit tomorrow or the day after.

This kind of disengagement brought about in Europe betrays the whole attitude of the Soviet Union to really create an area of confrontation, an area of tension on our borders, on Chinese borders and on the borders of all countries surrounding China and Soviet Union.

16 hrs.

Therefore, Sir, it is not a small matter. This has been done deliberately. I would like hon. Members of the House to appreciate one point. Of course, there may not be confrontation; but, assuming, there is confrontation tomorrow, a China-India confrontation, then, what will be the attitude of the Soviet Union in regard to that territory which they have passed over to China? What will be their stand? They have taken a position that these 58,000 kilometres of territory belongs to China. Therefore, I would like to ask this. Suppose there is confrontation in that area, which, according to Soviet maps, are shown as belonging to China, whether the Soviet Union will back us or whether the Soviet Union will back China? I feel that the Government should take note of it. The Soviet Union has committed itself to China, so far as these 58,000 KMs. of territory is concerned. It is all very simple for the Government of India to tell us that it does not matter.

I do not want to go into the details of what Shri Kanwar Lal Gupta said that Government has not made a very formal or informal protest in this regard. Sir, that is not a matter of concern. The matter of concern to us is this kind of deliberate action of the Soviet Union which is pregnant with very many serious implications.

The Soviet Union claims to be friendly to us. In this House we have commended the performance of Soviet Union so many times unanimously. But it is most unfortunate that the Soviet Union is now indulging in the internal politics of this country. It is time they understand that they should not be partisan in matters of concern with a friendly country, and in respect of internal matters, they should not interfere. We have that kind of understanding with the Soviet Union. We have commended the performance and the action of the Soviet Union *vis-a-vis* Kashmir.

I would sit down with these remarks. The Soviet Union has taken us for granted. Nobody is bothered about India. Whatever may be said about peace, or combination or cooperation or area of disengagement, who really bothers? The whole area of tension is brought to our borders. We are placed in a situation where the whole world has connived at us. That is why Soviet Union and America are telling us not to get armed or to go nuclear. They are putting pressure on us, because, they will arm the whole world but not India. They will arm Pakistan before our nose but not India. They always tell us, you disarm yourself; you are a strong country, in numbers, in population, etc. and therefore you should only talk about peace. By these methods, the area of confrontation has come to the borders of our country. There is a saying, when some want to weaken a nation, they make the neighbouring countries strong. Today they want to make Pakistan stronger. That is what Soviet Union is doing; that is what America is doing. That is what China is doing. Because, they have taken us as weaklings. They want us to be disarmed, whereas the Soviet Union and America and the countries whom they support have to be armed. They are arming everybody, roundabout India so that those countries may be stronger and we may be weak.

That is why Sir, I would submit to the Government to express the concern of the House seriously. There is one thing I would submit to this honourable House. We differed on many occasions. But this is a matter of concern which should be faced unanimously by this House. Let us really tell the Soviet Union that either they should stop this kind of publication and do not take our friendship for granted, or, else, we would consider this as a very unfriendly act of the Soviet Union towards this country. Thank you.

SHRI TULSIDAS DASAPPA (Mysore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have been hearing the arguments put forward by Shri Kanwar Lal Gupta and by Shrimati Tarkeshwari Sinha. It is quite understandable that they have got certain anxieties about the way in which some of the countries are trying to depict our maps and the way in which there seems to be some sort of distortion in the delineation of the boundaries of this country. But I must say that these friends who have been for a long time good students of history have not been able to realise the fact that perhaps very few countries are in a position to present an authentic map of another country; there is always some little change or discrepancy. Which you can find in these maps.

It is very interesting to find that even in the maps which have been produced by Peking and the maps that have been now used in Formosa, there is very little difference with regard to the delineation of Indian boundaries. These are things which are there, and we should not take these things in such an excited mood, but we should try to understand their difficulties also.

If you go into the particular instance about Russia, you will realise that at one time even Russia was able to present a map wherein Aksai Chin and the eastern boundaries on the Sino-Indian borders were being put under a question mark, which means that even Russia was not quite sure whether those portions of the land definitely belonged to India or China. This is the situation even in Russia. Of course, our notes have gone and our protests also have been given during the course of the last few years, and we must be happy to note that Russia has never been able to say that they stand by the maps which they have produced. They have also sent once a press release from Moscow wherein they have stated that there may be need for some modifications in the maps which they have drawn.

I would like to quote in this connection what the hon. Minister of External Affairs had said in this connection in the Rajya Sabha. He said:

> "The Soviet authorities in their replies have told us that this was a matter which was dealt within a technical manner by their cartographers and specialists. This need not, they have assured us, have any political significance; they have further told us that the Soviet Union completely respects India's territorial integrity and that wrong depiction of boundaries in such maps need not in any way affect or reflect Soviet Government's understanding of and respect for India's frontiers.".

Thus there is a clear commitment on the part of Russia with regard to their maps. I think that if this is the case, there should not be so much of justification for any anxiety or excitement on a matter like this, particularly for a person like Shri Kanwar Lal Gupta who is so much concerned about the territorial integrity of this country. I must say that he would not perhaps have been the right person to move such a motion as this at all because he belongs to such a political party that while the cartographers of a foreign country have made some mistakes with regard to the integrity of this nation in their papers, these are friends who have helped in promoting disintegration of the country by trying to rouse communal passions. They have even gone to the extent of

[Shri Tulsidas Dasappa]

trying to incite one State against another with regard to boundary disputes and small, little problems like that. I think these persons are a greater danger to the country than those who are not directly concerned with us but who might have shown a wrong delineation after taking the advice of their cartographers, who have got it wrong.

I take this opportunity to say that friendship between two countries also depends upon mutual consideration and respect towards each other. Whereas we have been fair to our neighbours, they should also reciprocate.

I go to the extent of saying that even if at all we are provoked on such small matters, we can as well fight with Ceylon over Kachchativu and we can fight with Burma over their showing some areas belonging to us as lying within their boundaries. (Now the boundary is being demarcated between India and Burma). Just because there are some distortions, we can go on fighting with them also. In this way, we may go on fighting with everybody ultimately losing all friends all over the world. This is the specific reason why we should not take so much serious notice of these things. At the same time, we should appeal to the Soviet Union to realise that we have our justification for our borders which have been there delineated for quite a long time and which have not been properly depicted in their encyclopaedia atlas and other documents. I do agree with some of our friends who have expressed their concern and said that there should be modification of the maps and proper correction carried out which would help our two countries to come much closer than we are today.

I would not like to repeat what my hon. friend, Shri Sant Bux Singh, has already said. But there are States like the USA, UK and a few other countries who have also not been very fair to us with regard to the depiction of our boundaries. It is not that we should try to aim at a particular country which is friendly and has been very helpful to us during the days of our difficulties, who have stood by us in our difficulties and who helped us even in our fight with China, for instance, by giving us military help around the time of the Chinese aggression.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): Who told him that?

SHRI TULSIDAS DASAPPA: It was after the aggression.

SHRI J. B. KRIPALANI: His history is very wrong.

SHRI TULSIDAS DASAPPA: Their attitude towards us has helped in better mutual understanding between our two countries. Therefore, we should weigh the pros and cons and look at the balance and not just take an isolated incident and make much of it against all the other positive factors of their help and assistance to us and the goodwill that we have been able to enjoy. One isolated incident should not be allowed to mar this relationship.

Therefore, taking account of these things, we should try to appeal to the good sense of all those countries including the Soviet Union to make corrections with regard to their erroneous maps as early as possible and try to foster the friendship which already exists between those countries and us.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): It is good that the House has decided to give its attention to this very important problem. I must frankly say that at first glance, I would have set aside this problem as an unimportant one.

I would have agreed with my friends who were arguing from the other side: "What is there if there is some mistake committed in a map published by some foreign country?

Why should we give any importance to it at all?" Probably an argument like this would have appealed to me in the beginning. I would have even agreed with the argument: "When a foreign country does it, how can we correct it? If they do not want to correct it, are we going to wage a war against them?" I would have in the beginning agreed with it. Then, as my hon. friend put it ,and even earlier Pandit Nehru also said: "This is only a map. Set it aside. Do not give any political significance to it. Unless and until our territory is occupied, why bother about it? In the last fifteen years they have been going on like this, and none of them has occupied our territory. Why bother or worry about it?" This sort of argument would have appealed to me in the beginning, but for certain important reasons which I would like to bring to the notice of the foreign Minister, why this matter is very serious and significant.

Had it been a case that 14,000 square miles of our territory had not been occupied by China, I would have considered this matter a trifling one. Had it been a case that a country like South America had published a map like this, I would have considered it a trifle and set it aside. Had it been a case that there was no possibility of occupation of our territory by any important neighbour, I would have considered this matter as a trifle and set it aside. But is that the case? Are we not having a border dispute? Are we not having our own territory occupied by foreign Powers? Do we not have territory in Kashmir occupied by Pakistan? Is there not a danger looming large the NEFA at any time may be occupied by China and we may be required to wage a war against them? In the context I do not want to take this matter lightly as some friends on the other side would like to consider it.

SHRI J. B. KRIPALANI: They take everything lightly.

SHRI R. K. AMIN: Yes, they take everything lightly and I cannot do so. Had there not been any border dispute with Pakistan and China, that might have been possible, but it is there and that is why I would like to take it very seriously.

I have certain specific reasons as well as general reasons for viewing this seriously and I would like to appeal to the Government that this matter should be taken up at the highest level, Let me discribe to you my specific reasons.

The matter has been going on for the last fifteen years and when the Government was asked whether they took any action, whether they sent any protest note to the Soviet Union at one time Government's spokesman says: "Yes, I have some impression that we have sent." When asked whether it is written or oral, he says: "We do not know whether it was oral or written, but some protest was made." Then it was said that they have now found that it was a written protest. When asked what the reply was they say they do not know what the reply is, but orally the Russians have said: "Do not give any political significance to that." Even when pressed on the Calling Attention in the Rajya Sabha to say whether they would try to get the reaction and the reply of the Soviet Union, Government says that probably the Russians might say: "No," in that case what is the fun in asking for a reply in a written way?" That is how it has been treated, and that is why it becomes very serious.

The second reason why it is serious is the precedent which has been created in Czechoslovakia. When Czechoslovakia was invaded, it was just a cartographic aggression. A psychology was created that a particular territory did not belong to Czechoslovakia but to somebody else. A second psychological attack was made by saying: "Lest West Germany should occupy it and take part of it, and we do not want to allow those re-

[Shri R. K. Sinha]

actionary forces to occpy, that is why was occupied it." Then lastly came the limited sovereignity doctrine of Breznev. I would like to ask whether the Foreign Minister can ask a friendly country like Russia: "You occupied Czechoslovakia so that West Germany may not do so. Now you have a treaty with West Germany. Are you going to vacate the territory of Czechoslovakia?" On that they will not speak. It means that by creating a particular psychological background they would like to occupy the country.

The methods of aggression have changed from time to time. The progressive will say that it should be by progressive methods. Now the latest method is that the brain-washing should be done of the main political figures in a country. Then the particular portion does not belong to them, and when they ask for it, some pretext should be created to occupy the country and you occupy it. That is how the Russian methods work. Lest they should adopt those methods in our country, we should take care.

From 1955 you have been committing the blunder. Probably two or three times the Government was asked why they were doing so. My friend Mr. Sant Bux Singh wanted to hide the mistakes of Russia and therefore pointed out the mistakes of the United Nations or America or Britain. But when you pointed out the mistakes to these countries have they corrected it or no? That is the real crux of the problem. Were they not ready to correct the mistake when you pointed it out to them? The Russians had been repeatedly told that they were not correct. What did they do? In 1965 when Shastriji was the Prime Minister, Russia did not put out any maps. In 1967 NEFA was shown in Russian maps as disputed territory. But after 1967, NEFA was indicated as Chinese territory. What is the intention of Russia in doing this? After all, it is a friendly country. Why should they continue to do so even when it was pointed out as a mistake?

There are probably two reasons. The first is this. There is dispute between China and Russia about their borders. China has indicated over a lakh sq. kms. of Russian area as its own. The Russians would like to reach some agreement with China by saying: if you vacate our territories, we shall be able to offer you others' territories; after all, you are concerned with the total territory and so it does not matter; you will get a big chunk there; why should we fight among ourselves?

That may be one reason. The second reason may be this. If we see our economic and political policies, it is clear that the Russians have taken us for granted. They seem to say: we are the big brother and if you commit a blunder it is our right to correct you. Perhaps the Government think that they will be able to safeguard our interests and that is why they advise us. I must point out that they are doing certain things deliberately after 1967. Why should not our Government take up the matter with them and say: NEFA is our territory; it has been accepted even by the United Nations.

When this Encyclopaedia was published even the American Press criticised it in May 1970. Between May 1970 and the time when the problem was taken up by us in August, what did the Government do? They simply slept over it; they just did not bother. It is a very serious matter and it ought to have been taken up in all seriousness. Unless it was corrected, we should not say that Russia is our big brother, or our friendly nation. In this context certain reasons appear to be valid. Take the economic policies. The entire public sector is dominated by Russians and I doubt if we have any say in the matter. If there is delay

in fulfilling certain commitments, is there a clause in your contracts with them that there will be some punishment or fine for the Rupssians? No. You have deposited your mind to them. The IDPL in Madras manufactures surgical instruments which fit only the Russian population, not the Indian population. Because the Russians could say, "you sell them away to us at throw-away prices," you subside them.

Take Bhilai. Our capacity of the structural production is up to 500,000 tons. Our demand in the country is hardly 100,000 honnes. Where can we sell 400,000 tonnes? They say you manufacture what we say, and you give us all that below cost, and how much is it? It is 45 per cent below cost! As if the Russians have given their factories to our country in order to manufacture their goods to be taken away by them at throw-away prices.

This is the situation in our economy. The situation is the same in respect of all the Russian collaboration with us. Take the other plants: the Heavy Electricals; the Heavy Engineering; even Bokaro and Bhilai. Take Surgical Instruments, and also the IDPL, Rishikesh and others. Everywhere, there is the same problem. Everyone of them is making losses, and where the Russian technicians are dominating, they do not allow you to speak even a single word. You do not have any say in them. If anything is clear, it is that we have made ourselves as serfs to the Russians in so far as our economy is concerned?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI R. K AMIN: Only one or two minutes. In the political sphere also, you take the foreign policy. So many of our friends have criticised our attitude towards Madame Binh. Was it not dictated by the Russians? Our attitude towards Rabat: was it not dictated by the Russians? Our denial to take part in the Jakarta conference; what is it not dictated by. Russia? Because Russia did not agree, we say we also do not agree. The entire foreign policy is like this; one by one, if you take any issue, it is all dictated by the Russians. If you take our domestic policy, you will find that whenever the question of the communist pary comes up,—what will be the attitude of Russia to the CPI—"Oh, we cannot displease the CPI because Russia would not like it; and so we have to make agreements.

Even in regard to its own embassy, their interest in contacting the MPs and entertaining them, they are using Sama, Dama, Dand and Bhed. We cannot do anything at all. On the contrary, we have to keep quiet: In short, they have dominated out domestic policy; they have dominated our foreign policy; they have dominated our economy. In this context, if you view this cartographic aggression, you will realise the seriousness of it. That is why my appeal to the Foreign Minister is that this problem should be taken up in right earnest. If the Russians do not correct the map, at least we can say that Russia is not our big brother; Russia is not a friendly country.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the previous speaker, instead of having the appearances of objectivity which his supporters on the other side had, again lapsed into a hysteria. What is the policy of our non-alignment? It is something which, for him, is in the laboratory of literates and he is political immature. The issues of Rabat and the issues of international policy are twisted and turned by him. It does not turn him when Taiwan publishes a map and commits cartographic aggression against India, their blood becomes loose and cold, when Saigon and Thailand, their brothers, publish maps which commit cartographic aggression against India. These gentlemen who echo like a cuckoo the voice of a particular international lobby, and who, even in this national lobby inside this

[Shri R. K. Sinha]

House would like to challenge the rulings of the Speaker, are farthest from the truth, away from the truth.

For the knowledge of these gentlemen, I have brought here a copy of the Encyclopaedia Americana, where the whole of Kashmir is shown as an independent territory, and yet these patriots keep quiet. (*Interruption*). Mr. Mody, I have a right to speak, and I shall exercise it. You will have your turn. I shall let you know what is the truth.

Mr. Deputy-Speaker, I condemn and I criticise the mistakes of the Soviet Union, but I do not want to be on parity with the hysteria with which Shri Mody and Shri Amin speak in this House. (*Interruption*). These are the gentlemen who would like to condemn the public sector taking over the purses of the princes. These are the people who trial behind the enemies of the poor man in India. They will condemn the Soviet Union but not the USA, Thailand, Taiwan and Swiss maps which are committing cartographic aggression against India year after year. If the Soviet Union has done anything wrong, we must say that they have done something wrong. But these gentlemen would like us to go to war with the Soviet Union. That is their hysteria. But we on this side are the friends of the people and we arrive at a decision on the merits of each matter, consistent with the honour of our country.

These gentlemen got a licking in Saigon. When Indians are beaten there, their blood does not boil. They may be beaten in the streets of Thailand and Taiwan and yet, they will say, Glory to Thailand and Saigon. We, as patriots, stand for the sovereignty and integrity of the country. But these foreign stooges, these potbellied people, downgraded by the Indian society, cannot govern our foreign policy. These widows and orphans of politics, who have been rejected by the Indian people and who shall be rejected, want to talk of non-alignment, sovereignty and defending the borders of this country!

They condemned our hospitality to Madame Binh. When the whole world believes that this small country, represented by Madame Binh, is fighting against the mightiest power in the world, these gentlemen would not pay a meritorious tribute to her. They would like Taiwan to be recognised. But they frown and say that the German Democratic Republic, which has got an elected Government and Constitution, should not be recognised. They talk of double standards and patriotism, Many of them did not think of Indian freedom when actual aggression on our soil was committed by the British. The Jan Sangh which parades nationalism today did not think of freedom in 1943 or 1945 or 1946. Their nationalism today is imported from western countries and they talk of patriotism.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल): हम तो 1930 में भी इस में थे, जब कि माननीय सदस्य पैदा भी नहीं हुए थे। आप क्या 1942 की बात करते हैं।

SHRI R. K. SINHA: You are talking about Gandhi. These are spiritual murderers of Gandhi. I was in the United Nations last year. On 5th October 1969, in the *New York Times* an article was published against Gandhi, which was a most shameful article. It was condemned by 5 Members of Parliament of the Congress Party who were there. But it was published in the *Imprint*, where Gandhiji has been murdered again. These gentlemen have not issued a statement against this. They talk of Gandhism and socialism. I know the crocodile tears they shed. (*Interruptions*). They have no principles and they have no future.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI: On a point of order, Sir. The discussion is about cartographic aggression

by Russia. Is there any relevancy in what he is speaking?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If every Member would cooperate in being relevant, I think, we would be a much more efficient House. Shri Kandappan.

SHRI PILOO MODY (Godhra): There will be silence then.

SHRI R. K. AMIN: May I make one submission? Shri Sinha has referred to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is all in the game.

SHRI PILOO MODY: He is accused of saying something that he did not say. I think, he should be allowed to correct it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No.

SHRI PILOO MODY: Why not?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No . . . . *(Interruption)*.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): He has made a charge against him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

SHRI SHEO NARAIN: * *

MR. DEPUTY-SPEAKER: All this will not go on record . .*(Interruption.* I think, what you all cartographic misrepresentation is more important than Shri Sheo Narain.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli): This is the last day. How can we forget Shri Sheo Narain?

SHRI S. M. BANERJEE: In the Russian map there has been photographic aggression of Shri Sheo Narain. His photo has been published . . . *(Interruption)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are paying too much attention to Shri Sheo Narain. He is not more important than the cartographic misrepresentation.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, whether we like it or not, the influence of the power that a country exerts over other countries depends upon the economic strength basically. Viewing it from that angle, we have to reconcile to the fact that our country does not enjoy so much prestige as many a time we seem to think is due to ourselves. It may satisfy our vanity to think that we have been exerting so much influence on certain areas or even to say that these are the areas where our influences are pervading. That is far from the truth. Unfortunately, we have got to recognise that fact. Within those limitations whatever an underdeveloped country can do diplomatically, was this Government able to do in the past or is doing at present, is the question I would like to pose.

I am sorry to say that even some of the small nations around us seem to have performed their diplomacy in a better way and succeeded in a more concrete way than we have succeeded so far. I would ask my friends opposite, particularly those who profess socialism and who are very vociferous as the previous speaker Shri Sinha was in supporting whatever is done by the Communist countries or the socialist countries, to be a little objective about these things.

We all know that at the time of the India-China conflict what that great Khruschev said. He categorised the Chinese as their brothers and India as their friends. That is the difference. We all know that blood is thicker than water.

As all the Members from this side have already pointed out, nobody would try to minimise the importance of the ties that we today have with Russia. But that does not mean that we should shut our eyes to hard realities.

What happened after the Indo-Pak. conflict? It is still green in our memory that one of the contributing

** Not recorded.

[Shri S. Kandappan]

factors towards psychological or popular more in favour of our friendship with Soviet Russia was that, all along, Soviet Russia was using their veto power in our favour as against Pakistan when the issue of Kashmir came up in the Security Council. But even that was suspected and Russia came openly to support Pakistan. Then, of course, our people protested and ultimately we had to swallow it.

After that, the question of cartographic aggression has come about. There is no use in satisfying ourselves with the feeling that Russia is after all a friendly country and that our approaches or diplomatic moves in an inoffensive way will help to improve the things. I do not think they are going to improve that way. We have got to be a little more firm and categorical in these things. If we are going to live with the feeling that we have to take things lying down, either it is Russia or U.S.A. or U.K. or any other big power, because of our economic conditions, I am afraid, no country is going to respect us. I am rather sorry to say that one Member from the ruling Congress said, "After all, what is there in a map? It is a small thing. We need not make a big fuss over it." I remember, in 1962 and after that, 1965, during the conflict with China and Pakistan, there was a lot of furore raised in the House and no less a person than Mr. Bhagwat Jha Azad—he was an ordinary Congress Member at the time; he was not in the Council of Ministers then—moved a resolution that we should sever our ties with the Commonwealth because the U.K. press was supporting Pakistan....

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah): I would like to say one thing. That might be the opinion of an individual Member from this side, not of the Congress party.

SHRI PILOO MODY: Are you disowning him? You can get up and say, "We disown him."

SHRI S. KANDAPPAN: At that time, from the Congress Benches, Mr. Bhagwat Jha Azad moved a resolution that we should sever our ties with the Commonwealth on the ground that the B.B.C. and the press in U.K. was publishing a lot of material against India, damaging the image of this country. If this sort of an argument that is advanced about the map, could have been very well advanced for that propaganda also saying, "Why do you care if any country is carrying on propaganda against you. Ultimately, it depends on our strength." We could equally say that. But that will be a ridiculous sort of an argument. Whether it is the question of a map or propaganda, from whatever quarter it comes, we cannot be complacent about it. This is a very serious matter. I would rather appeal to the hon. Minister to view it from that angle.

I feel there is definitely a shift in the Soviet angle. I do not think they have completely tried to alienate us or we have lost our friendship with them. As somebody has already pointed out, they have taken us too much for granted or they think that our friendship is rather easy. that we are such a simpleton or innocent that, probably, what the world thinks about it is that they can just with impunity offend us, whether it is cartographic aggression or otherwise. It is high a time when we should try to chalk out our own way within of course, as I have already said, our limitations.

Then, I would like to point out another very important factor. This Government has got to be blamed about it. I remember, in this House, Dr. Lohia raised the question about the map published in our own country, leave alone the foreign countries. He raised the discussion and different figures were given in terms of so many miles and kms. and the Government of India did not agree with those figures..

SHRI PILOO MODY: Like the voting figures.

SHRI S. KANDAPPAN: I don't agree there.

Dr. Lohia raised that issue and, at that time, the Minister was Mr. Chagla. When he gave a reply, he was not able to give a convincing reply. Actually, they were wavering. They said the topography was not clear. It has to be further clarified and further research has to be done and the Surveyor of India was at it.

So, I feel the Government of India itself is lacking in its proper approach to these basic problems and as was pointed out, it does not matter so long as we do not have enemies on our borders. But, once a question of aggression comes and when there are border disputes and there are potential and actual enemies on our borders, it is all the more necessary and important for us to be careful on these issues.

I would again beg of the Minister to be a little more serious about this problem. I would beg of my friends on the opposite who think that the Soviet friendship would also help us. Certainly, without minimising our friendship I am afraid that alone will not help us. If you give an impression either to the Soviets or to any other country in the world that you are helpless, that you are innocent, that you could be easily won over by small mercies and you are not too demanding or you are not intelligent enough to protest even on rightful matters, then they will take you for granted and with impunity commit cartographic or any aggression they want. So, this is the crux of the matter and we have got to view that in that angle.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चर्चा उठाई गई है, मैं समझता हूं इस माने में मौजूद है कि यद्यपि प्रस्तावक महोदय की नीयत उल्टी रही फिर भी हमको यहां पर चर्चा करने का मौका मिला है। मैं यहां पर अपने दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक नक्शे का मामला है, भारत सरकार द्वारा छाप गए नक्शे को हम सही मानते हैं। उससे अलग संसार का कोई देश भी नक्शा बनाये, वह चाहे हमारा गहरा दोस्त ही क्यों न रहे या मामूली दोस्त ही रहे लेकिन हम किसी भी दूसरे नक्शे को नहीं मानते। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की सरकार द्वारा जो नक्शा छपाया गया है जोकि हमारे अपने भारतीय नक्शे से अलग जाता है, हम उसको नही मानते। हम भारतीय नक्शे को ही मानते हैं।

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

इसके साथ ही मैंने यहां पर कुछ सदस्यों को जो सुना, मैं मान लेता हूं कि अनजाने ही कुछ लोगों ने ऐसा कहा लेकिन क्या इससे हम यह नतीजा निकाले कि सोवियत संघ की नीति में परिवर्तन हो रहा है—जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। कुछ लोगों को ऐसी आशंका हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि पहला एतराज भारत सरकार ने नक्शे के बारे में सन् 1956 में किया था जबकि सोवियत संघ ने यह नक्शा छापा था। उसके बाद दोबारा और तीबारा एतराज किया गया और अब चौथी बार इन 15 सालों में एतराज हुआ है। अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो फिर हमें 15 साल पहले तक जाना पड़ेगा क्योंकि वह चीज फिर इस बीच की नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि परराष्ट्र मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यह नया नक्शा है जोकि सोवियत संघ ने छापा है या यह वही पुराना नक्शा है ?... **(व्यवधान)**..... मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि क्या यह वही नक्शा है, यानी चीन में आज जो जनवादी गणतन्त्रीय सरकार है, जब उसकी स्थापना भी नहीं हुई थी, उससे पहले वाला नक्शा है ?....**(व्यवधान)**...

दादा (आचार्य कृपालानी) हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं ? आपने जीवन भर पूंजी का त्याग करके भी पूंजी वालों का समर्थन

श्री भोगेन्द्र झा]

किया है और हमें आशा है कि अब अन्तिम समय में भी पूंजी वालों का त्याग करेंगे।... (व्यवधान) ....

श्री० जी० भा० कृपालानी : मैं यह बताना चाहता था कि सन 1956 में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चाइना में थी।

श्री योगेन्द्र झा : मैं श्री कृपालानी की जानकारी के लिय कहना चाहता हूं, क्योंकि जानने के बाद भी वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक समय कहा था—जब चीन का हमला हुआ था और हमारी फौजें हट रही थीं, अमरीका काश्मीर छोड़ने के लिय कह रहा था, ऐसे कुछ लोग थे, जिन्होंने कहा था कि काश्मीर छोड़ो। चूंकि कम्यूनिज्य के सिद्धान्त की लड़ाई हैं इस लिये काश्मीर छोड़ो। ऐसा कहने वालों में श्री कृपालानी भी थे उस समय उन्होंने कहा था। उस समय हम ने कहा था कि हमारा चीन से झगड़ा सरहद के लिये है, सीमा के लिए है, कम्यूनिज्म के खिलाफ नहीं है। सिद्धांत के लिये कम्यूनिज्म के खिलाफ जो लड़ाई होगी वह यहां होगी, पार्लियामेंट में होगी, भारत में होगी। हमारा झगड़ा चीन से सरहद का है। चूंकि यह मामला सरहद का है, इस लिये हम यहां बहस कर रहे हैं। श्री कृपालानी कम्यूनिस्ट राज्य की बात कहते हैं। मैं चाहता हूं श्री कृपालानी दीर्घायु हों ताकि वह भारत में भी उस को देख लें **(व्यवधान)**

मैं आज यह जानने का आग्रह करूंगा कि जो नक्शा सोवियत संघ ने छापा है या जो पता आया है क्या उस नक्शे में चन चांग घाटी भी है जिस को चीन की सरकार अपने नक्शे में अपना मान रही है लेकिन सोवियत संघ के नक्शे में वह भारत का हिस्सा दिखलाया गया है? कि क्या वह नक्शा चांग काई क के जमान में चीन में छपा था वही नक्शा है, जो हमारे दक्षिण पंथी मित्रों के गुरू या नये देवता हैं, जो दौड़ दौड़ कर ताइवान जान में नया मजा पात हैं। वह मजा उन को मुबारक।

एक माननीय सदस्य : आप को वह मजा नहीं आता है ?

श्री भोगेन्द्र झा : आप वहां जल्दी हो आइये नहीं तो वहां भी जान की जगह नहीं रहेगी। **(व्यवधान)** यह पुराना नक्शा है, वह चीन का 1947 से पहले वाला नक्शा है तो इस पृष्ठभूमि में मैं समझता हूं कि पर-राष्ट्र मंत्री को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये, जिससे वह साफ हो कि यह नक्शा सोवियत की भारत के प्रति नीति में परिवर्तन का प्रतीक नहीं है। अगर वह साफ न हो तो उसकी सफाई वह ले लें। अगर कोई कहे कि सोवियत संघ में किसी की गलती से यह नक्शा छप गया तो मेरे ख्याल में शायद ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह लगातार की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत संघ का ऐसा रूख रहा है कि जब तक भारत और चीन का विवाद है तब तक वह नया नक्शा नहीं छापेगा, न इधर का न उधर का, और इसी लिये वह 1947 के पहले वाला नक्शा छाप रहा है। यह बात गलत है या सही यह स्पष्ट हो जाना चाहिये। वह कहते हैं कि इस का कोई महत्व ही नहीं है, किसी की गलती से हो गया। इस के साथ ही मैं इस पर भी जोर देना चाहता हूं कि जो चांग काई शेक के जमान का पुराना नक्शा है क्या आज की चीन की मौजूदा सरकार का नक्शा उस से भिन्न है? इस सम्बन्ध में भी हम ने चिन्ता जाहिर की है। हमारे लिये यह चिन्ता का विषय है। मैं इस को कम नहीं करना चाहता, बल्कि इस का और भी इजहार किया जाय, जैसा कि पर राष्ट्र विभाग के मंत्री ने किया है, इस में कोई दो राय नहीं हैं।

लेकिन आज इस बात को उठाने का मतलब क्या है ? क्या जनसंघ के सदस्य लोग चाहते हैं कि सोवियत संघ से सांस्कृतिक सम्बन्ध तोड़ लिया जाये ? जो कुछ श्री गुप्त ने कहा, मैं समझता हूं कि वह एक ऐसी अभारतीय संस्कृति है, जिस की पहली चोट संस्कृति पर पड़ी। जो भारत की मानवतावादी संस्कृति से ही संबंध तोड़ना चाहते हैं उन के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पता नहीं उन्होंने विचार कर ऐसा किया या बिना विचारे किया । आज दुनिया में प्रमुख साम्राज्यवादी देश भारतीय भूखण्ड को विकृत रूप से पेश कर रहे हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र के नक्शे की बात नहीं कह रहा हूं। लगातार 23 वर्षों से अमरीका और ब्रिटेन इस बात पर अड़े हुए हैं कि जम्मू और काश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह शर्म की बात है।

श्री भोगेन्द्र झा : आप के लिये यह शर्म की बात है इस की खुशी है, लेकिन हमारे लिए यह शर्म की नहीं गुस्से की बात है। इस लिये काश्मीर के लिये दो बार प्रस्ताव पास कराये गये, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ दल हैं जिन्होंने कहा कि काश्मीर छोड़ दो। आज भी गोआ के नाम पर एक प्रतिनिधि पुर्तगाल की तथाकथित पार्लियामेंट में बैठता है। अमरीकी सरकार गोआ को भारत का भू भाग नहीं दिखलाती है। पुर्तगाल से गोआ को ले कर सरहद का झगड़ा नहीं है, गोआ के उस पार पुर्तगाल नहीं है। आज भी अमरीका उस को भारत का भाग नहीं दिखलाता है, लेकिन सदस्यों ने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : किया है।

श्री भोगेन्द्र झा : नागालैंड का फीजो बागी बन कर विलायत में है। विलायत की सरकार ने अभी उस को अपना नागरिक बना लिया है। यह मामला सरहद को ले कर नहीं है, हमारे भूखण्ड का मामला है, गणतन्त्र के अस्तित्व का सवाल है। काश्मीर के रहने या जाने में भारतीय गणतन्त्र के चरित्र का मामला है, नागालैंड के रहने या जाने में भारतीय गणतन्त्र के चरित्र का सवाल है। गोआ का सवाल भी इसी तरह का है।

इसी पृष्ठभूमि में हमारी स्वतन्त्र पार्टी के मित्र ने औद्योगिक विकास पर चोट की है। हम जानते हैं कि उन का हमारी सरहद से ताल्लुक नहीं है। वह सोचते हैं कि मुनाफा किस में बैठता है और घाटा किस में बैठता है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा। श्री गुप्त ने जो संस्कृति की बात कही, वह भी पूंजी का मामला था। चूंकि राजकीय क्षेत्र बढ़ने से मुनाफे में कमी आती है इस लिये उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। क्यों सोवियट संघ सहायक है बोकारो को खड़ा करने में, हटिया, भिलाई और लड़ाकू विमान का कारखाना लगाने में या चार स्क्वैड्रन पनडुबी जहाजों को दे रहा है ? इस लिये कि हम हिन्द महासागर में शक्तिशाली न हो सकें, यह साम्राज्यवादियों के लिये चिन्ता का विषय बन गया। स्वतन्त्र, जनसंघ और सिन्डीकेटी कांग्रेस के सदस्य उसी चिन्ता का इज्हार सदन में करते हैं।

जहां तक हमारे नक्शे का मामला है, भारत जो नक्शा रखता है एक मत से उस की सदन में पुष्टि हो यद्यपि उसकी जरुरत नहीं है, लेकिन इसको दोहराते हुए मैं साथ साथ यह भी आग्रह करुंगा पर-राष्ट्र मंत्री से कि वह सदन के सामने, आज करें सकें तो आज करें, नहीं तो बाद में कर, लेकिन यह बतलायें कि संसार में कौन-कौन से देश हमारे भूखंड के बारे में कैसे कैसे नक्शे छापते हैं, खासकर प्रमुख देश जैसे सोवियत संघ हैं, संयुक्त राज्य अमरीका है, ग्रेट ब्रिटेन हैं। वह चकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में चिन्ता न करे। संसार के पूंजीपतियों ने अनुमान लगाया था कि

[श्री योगेन्द्र झा]

पूंजीपति वहां फिर राज्य करेंगे, लेकिन वह नाकाम हो गये। मगर हमारे यहां वाटा कम्पनी बढ़ रही हैं। आज वह इत्मीनान रक्खे कि जहां मजदूरों का राज्य हुआ है वहां वह उलटन नही पायगा संसार भर के श्रमिक एक हो कर खड़े हो जायेंगे और मजदूरों के राज्य विरोधी चकानाचूर हो जायग। उन का सपना चूर हो जायगा :

आज सोवियट संघ के बारे में जो शक किया जाता है कि अगर चार बार इन्होंन आग्रह किया, खेद जाहिर किया और स्पाट जवाब नही मिला तो क्यों नही मिला। हम इस बात को गम्भीरता से सोंचे : क्या इस लिये कि अमरीका हम को आक्रमण कारी कहता है, गोआ पर आक्रमणकारी कहता है, काश्मीर पर आक्रमणकारी कहता है और कहता है कि हम लोग वहां से हट जाय ? फिर भी हमारी सरकार अमरीका की सरकार के सामने जम कर विरोध नही करती। कि इंग्लैंड के ट्रेनिंग पाये हुए डाक्टरों के हाथों में हमारे औजार नहीं आते और वह अपने कारखानों को बन्द करना चाहते हैं ? म हमारा अपना मद्रास का कारखाना खराब कहा जाता है क्योंकि विलायती हाथ उस पर चलते नहीं ? आज विलायती और अमरीकी साम्राज्यवादी परम्परा के मुताबिक हिन्दुस्तान के इजारेदार और पूंजीपतियों के तबके हिन्दुस्तान की आजादी पर खतरा डाल रहे हैं औद्योगिक विकास पर खतरा डाल रहे हैं, हमारे जनतन्त्र पर खतरा डाल रहे हैं, आज सुबह से शाम तक जो राजाओं की थैली के विषय में मतदान पर विवाद हुए उन मे पालियामेंट के पुजारी उस के नाम पर आंसू नहीं वहा रहे हैं, बल्कि एक तरह से बगावत कर रहे हैं। एसी स्थिति मैं प्रचार के वहाने यह लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोवियत संघ से दोस्ती तोड़ो ताकि यहां पर थैली का अखण्ड साम्राज्य सब दिन काम रहे। नतीजा यह है कि जिस तरह से साम्राज्यवादी हमारे भूखंड को 200 सालों तक गुलाम बनाय रहे उसी प्रकार अब भी गुलाम बना कर रखेंग। इस लिये पर-राष्ट्र विभाग की ओर से देश के सामन इस समय जो सभी देशों के नक्शे हैं....

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : आज तो सोवियत नक्श की बात है, और नक्शे दिखान की बात नहीं है।

श्री योगेन्द्र झा : इस लिये मेरा कहना है कि परराष्ट्र विभाग और यह सदन अपने साथी दशों को तोल ले कि कौन हमारा कितना दोस्त है, अठन्नी चवन्नी, रूपया और उस के बाद अपनी नीति बनाने मे मदद करे।

इन शब्दो के साथ जो मूल मोशन है मैं उस का विरोध करता हूं और श्री बनर्जी के मोशन का समर्थन करता हूं।

SHRI UMANATH (Pudukkottai): I rise to disapprove of Shri Kanwar Lal Gupta's disapproval motion. The Soviet Encyclopaedia has reproduced a map showing Aksai Chin and NEFA as part of China. I think the conduct of the Soviet Government is more in the nature of continuing its old maps pending final settlement between India and China . . .

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha): Why do they not say that?

17 hrs.

SHRI UMANATH:...... rather than an indication of its thinking on the merits of the dispute. Now, if we demand, be it the Government of India or any party, that the USSR should discontinue the old maps and re-introduce new ones, then it means that the Soviet Union is called upon to determine what belongs to us and what belongs to China and on that basis re-draw the maps.

If a third country thinks that it will not be proper for it to determine what should go to India and what to China, if it thinks that it is better settled by the two countries mutually and that it shall leave its maps undisturbed pending such settlement, I do not understand how that country is wrong unless we want to deny that country its own sovereign right to take decisions which we claim for ourselves. The essence of their demand is something else. It is that when there is a dispute between India and China regarding our borders, all countries who want friendly relations with us shall accept what we consider to be our borders and recast their maps according to our stand as otherwise we will have no relations with them whatsoever. At this rate, there can be no international relations not only with China or Russia but with any other country in this world. You will have to look to the space and to the moon for relations and not with any country on the face of this earth.

Hon. members who were fuming and fretting on this want to make it appear that their enmity towards the Soviet Union is due to the Soviet Union's so-called cartographic aggression. No. It is the other way. Their theory of cartographic aggression was the by-product of their political and ideological enmity with the Soviet Union. Nor is their anger about this map arising out of their concern for our borders. The Chiang Kai-shek government have published a number of maps showing Aksai Chin and NEFA as parts of China, similar to the ones published by the Soviet Union. Where did the love of our borders of these gentlemen disappear? Perhaps it melted away in the warm embrace of Chiang Kai-shek. What is more, the refugee of Chiang Kai-shek, Formosa, has become the Mecca for these people. The tongues which call into question friendly relations with the USSR over these maps call for establishment of diplomatic relations with Chiang Kai-shek despite his publishing similar maps.

Some friends have already said that the USIS has published a number of publications excluding Kashmir from Indian territory. I want to know why our cartographers got cold feet which otherwise should marked to the US embassy here. In other words, it is international ideological ganging up which parades as national patriotism on this issue.

To the Government, I would like to say a few words. Do not forget that these maps of various countries or the non-changing of the old maps are off-shoot of the continuance of the dispute between us and China. The late Prime Minister, Pandit Nehru, himself had gone on record under international gaze expressing no objection to arbitration on this question in his correspondence with the Chinese Government, thereby by implication admitting the existence of the dispute. If other countries take cognisance of this statement or correspondence of Pandit Nehru relating to the existence of this dispute and take up the position of not disturbing the old maps pending a settlement of the dispute, why blame them?

The real solution of the map problem lies in a lasting solution of the dispute between our country and China. Instead of looking at this problem in this light, Government are going about with a can of black tar in hand; wherever they come across such maps emanating from any country as part of their publications, they are smeared with tar. I do not know since when this Government became a faithful convert of Shri E. V. Ramaswamy Naicker who went about with a can of tar to smear Hindi letters in Tamil Nadu.

When these very maps are circulated in millions of copies throughout the world, do you think your smearing them in India will do away with this problem?

[Shri Umanath]

Recently the Government have gone a step further by prescribing all these maps. This is nothing but succumbing to anti-Soviet and anti-China reactionary pressures in this country. Let Government stand up to these pressures, take a bold initiative to settle our dispute with China; the correct maps will automatically follow and emanate from all countries.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले हम को बाहर एक चिट्ठी मिली कि दिल्ली के समाजवादी युवजन सभा के पंद्रह लड़के पटेल चौक पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वे लोग मांग कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़कों को यूनियन बनाने का अधिकार हो . . . .

सभापति महोदय : इससे इसका क्या संबंध ह ।

श्री जनेश्वर मिश्र : इसी से मैं इसका सम्बन्ध जोड़ रहा हूं । श्री राज कुमार जैन जिन्होंने हिन्दी मे इम्तहान दिया था, उसके लिए व मांग कर रहे थे कि उसकी कापीयां जांची जाए। लेकिन इस सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। स्वर्ण सिंह जी चूंकि विद्यार्थी उनके सामने कमजोर पड़ते हैं इस वास्ते उनको तो पकड़ कर बन्द कर देते हैं लेकिन मजबूत रूस जब हमारे देश की धरती के नक्शे को बिगाड़ देता है तो सिर झुका लेते हैं। यह है इस सरकार की नीति।

नक्शे का महत्व क्या होता है ? पिछले बीस साल से इस देश की सरकार के सामने केवल कुर्सी का महत्व रहा है, देश की धरती के नक्श का महत्व नहीं रहा है। विदेशों में इस देश को तीन तरह से अपमानित किया गया है। एक तो हमला करके, दूसरे प्रकाशनों के जरिये और तीसरे हिन्दुस्तान के लोगों को अपन देश की धरती पर वहां अपमानित करके। हमारी पार्टी के नेता डा० राम मनोहर लोहिया को अमरीका के होटल मे जान से रोक दिया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वह काले थ। आपने इसको इस देश का अपमान महसूस नहीं किया। बहुत से हिन्दुस्तानी आज भी अफ्रीका के देशों मे अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप याद रखें कि कमजोर और बेईमान देश की धरती रबड़ की धरती होती है। बेईमान शब्द का प्रयोग मैं आपके लिये नहीं कर रहा हूं, और देशों के लिये कर रहा हूं। जो साम्राज्यवादी देश होते हैं वे बईमान कहलाते हैं। उनकी धरती सिकुड़ती भी है और बढ़ती भी है। मजबूत, स्वायत्त, स्वतंत्र और सर्व प्रभुत्ता-सम्पन्न देशों की धरती हमेशा फौलादी धरती हुआ करती है, वह न सिकुड़ती है और न बढ़ती है। हिन्दुस्तान की धरती सिकुड़ी है। काश्मीर मे सिकुड़ी है। सन, 1947 मे बटवारे के समय सिकुड़ी है। हिमालय की सरहद पर सिकुड़ी है। कच्च मैं सिकुड़ी है। कच्चाटिवू मे सिकुड़ने जा रही है। इतना बड़ा अपमान देश की धरती के नक्शों तथा हमलों के समय आपने किया है, असली धरती पर किया है आपन कागज के नक्शों के महत्व को बेकार किया है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि अमरीका ने गलत नक्शा छापा, स्विटजरलैंड ने गलत नक्शा छापा, तब एतराज क्यों नहीं किया। मैं कहूंगा कि अगर देश की सरकार मैं दम है तो एक साथ वह निन्दा करे अमरीका की, स्विटजरलैंड की और रूस की भी। तीनों की वह निन्दा करे। हिम्मत के साथ निकले और कहे कि क्यों ये नक्शे बिगाड़ते हैं। असल मैं इस सरकार ने पिछले बीस साल में जान-बूझ कर इन नक्शों के महत्व को कम किया है। जब चीन ने हमला किया था हिमालय की सरहद पर, हमारे देश की धरती जब सिसक रही थी उस समय इसी सदन मैं प्रधान मंत्री ने कहा था कि जिस धरती पर चीन

ने कब्जा किया है वह धरती कंटीली है, पथरीली है । अपनी धरती को हम भारत माता कहते हैं । उसके किसी भाग पर विदेशी कब्जा करे और मां का सब से जिम्मेवार बेटा कहे कि मां की उंगली—ये डा० लोहिया के शब्द हैं जो उन्होंने लोक सभा में कहे थे—सब से लाड़ला बेटा कहे कि मां की उंगली सड़ी हुई थी जिसे विदेशी ने पकड़ लिया है, इससे बड़ा अपमान और कुछ क्या हो सकता है ? मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार ने जानबूझ कर देश के नक्शे को अपमानित कराने की साजिश की ।

अभी बहस होने वाली है हरिजन लोगों के सवाल पर । वह सवाल आएगा या नहीं मैं नहीं जानता हूं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं । गांव में हरिजन बसता है गांव के दक्षिणी टोले में । चमरौटी उसको कहा जाता ह । गांव के उत्तरी टोले में ब्राह्मण ठाकुर बसता है । बीच मे बनिया , कुर्मी, काछी अहीर आदि लोग बसते हैं । अब आप दुनिया के नक्शे को देखें । अमरीका से ले कर यूरोप होते हुए रूस तक यह ब्राह्मण, ठाकुर वाला उत्तरी टोले का मुहल्ला है । बीच में चीन ईरान, ईराक, मिश्र यह बनियों, कुर्मी आदि का मुहल्ला है । हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा अफ्रीका, इस में हरिजन बसत हैं । उत्तरी टोले में जहां ठाकुर , ब्राह्मण आदि बसते हैं उनको हम कानूनगो, पटवारी, पंडित अमीन कह सकते हैं । उत्तरी टोले के अमीन कभी कभी हरिजन के खेत के नक्श को बिगाड़ दिया करते हैं । इसको ले कर दक्षिण टोले के हरिजन जब आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में लेन देन के सवाल पर झगड़ा करते हैं, या एक दूसरे की बहू बेटी की इज्जत के सवाल पर झगड़ा करते हैं तो ठाकुर साहब शराब के नशे में, जब नीयत खराब होती है तो रात को पान खाते हुए और छड़ी हाथ म ले कर आ जाते हैं और कह देते हैं चुप बे, लड़ाई बन्द करो और दोनों सटक कर चुप्पी लगा लेते हैं । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई चली । वह देश की सरहदों के लिए लड़ाई थी, राष्ट्रीयता जूझ रही थी, अब्दुल हमीद जैसे जवान शहीद हो रहे थे, पैटन टैंक टूट रहे थे और उसी समय मास्को में ठाकुर साहब की नीयत खराब हुई, उन्होंने कहा चुप बे, लड़ाई बन्द करो, दोनों ने सटक कर चुप्पी लगा ली । दुनिया में और भी लड़ाइयां हुई हैं । वियतनाम में हुई है, कम्बोडिया में हुई है । क्यों नहीं किसी देश ने, ठाकुर देश के आदमी ने उसी तरह से जिस तरह से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान से झगड़े में पंचनामा किया था, उसी तरह दूसरे देशों के झगड़ों में पंचनामा किया ।

क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि जिस तरह से इस देश का नक्शा दूसरे देशों द्वारा बार-बार बिगाड़ा गया है, क्या दुनिया के किसी और देश के नक्शे को उसी तरह बिगाड़ा गया है ; अगर नहीं बिगाड़ा गया है, तो इस के लिये जिम्मेदार कौन होगा ? मंत्री महोदय होंगे या कोई दूसरा होगा, मंत्री महोदय इस पर विचार करें ।

मैं बहुत ही ईमानदारी से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लड़का अपनी मां की इज्जत की रखवाली नहीं कर सका, उस लड़के को अपनी मां का मालिक बनने का कोई हक नहीं है । हिन्दुस्तान की धरती भारत माता है । इन बीस बाईस सालों मे इस सरकार ने भारत माता को अपमानित करवाया है । कल प्रधान मन्त्री और श्री चव्हाण ने वक्त के तकाजे की बात कही थी । आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वक्त का तकाजा है कि हिन्तुस्तान का जनता इस सरकार को गद्दी से उखाड़ कर फेंक दे, वर्ना भारत माता की इज्जत इसके हाथों मैं नहीं बचेगी ।

साथ ही में रूस, अमरीका और ईगलैंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता अपने देश की धरती की हिफाजत करना भी जानती है । सरकार निकम्मी हो सकती है , लेकिन जनता बहादुरी से उस

[श्री जनेश्वर मिश्र]

अंग्रेज से लड़ चुकी है, जिस का सूरज दुनिया में कहीं नहीं डूबता था । अगर यह नक्शा ठीक नहीं किया गया, तो रूस का कोई भी अधिकारी हिन्दुस्तान की धरती पर बिना काले झंडों का स्वागत लिये नहीं जा सकता है। अगर अमरीका और इंगलैंड इस देश का गलत नक्शा बनाते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता को फैसला करना पड़ेगा कि इस धरती पर उन देशों के आदमी आजादी से न चलने पायें ।

सभापति महोदय : आखिर में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि चाहे दस बजे रात को ही क्यों न हो, हरिजनों के सवाल पर जरूर बहस कराई जाये, क्योंकि वह देश के बहुत ही ग़रीब लोगों का सवाल है । अगर वह सवाल अछूता रह गया, तो यह देश भी इसी तरह अपमानित होता रहेगा

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि पिछले वर्षों में रूस में जो हिन्दुस्तान के जो नक्शे प्रकाशित हुए हैं, उन में हिन्दुस्तान के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है । इस को सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है । प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का ग़लत नक्शा प्रकाशित किया, तो एक सरकार की हैसियत से भारत सरकार का जो कर्त्तव्य था, उस ने उस को निभाया है या नहीं और अगर निभाया है, तो किस प्रकार से निभाया है ।

जब भारत सरकार का ध्यान रूस में प्रकाशित उस नक्शे की तरफ गया, जिस में हमारे देश के कुछ भाग को ग़लत ढंग से दिखाया गया था, तो उस ने 1956 में ही, जब कि न तो भारत और चीन की लड़ाई का सवाल पैदा हुआ था और न ही रूस और चीन की सरहद का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस से प्रोटेस्ट किया । इस के बाद 1958, 1967 और 1968 में भारत सरकार ने लगातार चार बार रूस सरकार से लिखित रूप से प्रोटेस्ट किया कि हमारे नक्शे को ठीक से नहीं दिखाया गया है । जिस नक्शे को ले कर यह चर्चा हो रही है, जब उस की ओर भारत सरकार का ध्यान गया, तो उस ने जून, जुलाई और अगस्त में, लगातार तीन बार, अपने राजदूत के माध्यम से, और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आये, उन से बातचीत कर के, इस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उस ने रूस देश का नक्शा ठीक नहीं दिखाया है ।

प्रश्न यह है कि जिस नक्शे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस के बारे में हमें चिन्ता होनी चाहिए या नहीं । मैं समझता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा नक्शा सही ढंग से नहीं दिखाता है, तो स्वाभाविक रूप से देश को उस के बारे में चिन्ता करनी चाहिए । हम अपने कर्तव्य से चूक नहीं सकते हैं । लेकिन जहां तक इस चर्चा का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य, श्री कंवरलाल गुप्त, की तारीफ़ और प्रशंसा करता, अगर वह उन तमाम देशों का जिक्र करते और निन्दा करते, जिन्होंने हमारे नक्शे को ग़लत ढंग से दिखाया है । मैं नहीं जानता कि संसार के किन किन देशों ने किन-किन देशों के नक्शे ग़लत दिखाये हैं । उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है कि रूस, इंग्लैंड और मिश्र उस के नक्शे को ग़लत दिखाते हैं । हमें शिकायत है कि हमारे देश के नक्शे को केवल रूस ने ही नहीं, बल्कि यू० एस० ए० ने भी ग़लत दिखाया है । जिस काश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आये हैं, जिस के बारे में हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, अमरीका उस काश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में या पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाता है । लेकिन अगर माननीय सदस्य,

श्री कंवर लाल गुप्त, अपने पूरे भाषण में उस की चर्चा भी नहीं करते हैं, तो मैं उस का क्या अर्थ लगाऊं ? अगर वह इस बात का जिक्र भी नहीं करते कि कई अन्य देशों ने हमारे नक्शे को ग़लत दिखाया है, तो मैं उस का क्या अर्थ लगाऊं ? **(व्यवधान)**:

श्री रणजीत सिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य देखें कि सदन के सामने मोशन क्या है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभी पार्टियों के सदस्यों को बोलने का टाइम मिल रहा है। जो कोई सदस्य इस के बाद बोलेंगे, वह इन बातों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस तरह बीच में इन्टरफ़ीयर कर के टाइम बर्बाद न किया जाये।

श्री रणजीत सिंह : मेरा पायंट आफ़ आर्डर है । सदन के सामने जो मोशन है, वह रूस द्वारा छापे गये भारत के नक्शे के बारे में है । माननीय सदस्य को उसी विषय तक सीमित रहना चाहिए। अमरीका द्वारा छापे गये गन्दे नक्शों के बारे में पच्चीसों बार यहां बहस हो चुकी है, जो हमारी पार्टी ने उठाई है, डा० लोहिया ने उठाई थी । कोई यह कैसे कह सकता है कि वह प्रश्न कभी नहीं उठाया गया ? माननीय सदस्य के पक्ष के लोगों ने भी उस प्रश्न को उठाया था । सब लोगों ने उस की निन्दा की है।

सभापति महोदय : यह कोई पायंट आफ़ आर्डर नहीं है ।

श्री रणजीत सिंह : पायंट आफ़ आर्डर यह है कि जो विषय सदन के सम्मुख है, माननीय सदस्य को उसी पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं ।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली): अगर पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करे, तो माननीय सदस्य कहेंगे कि पहले चीन से लड़ लो, फिर पाकिस्तान से लड़ना !

सभापति महोदय : आप की पार्टी के सदस्य बोल चुके हैं। अब माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री चंद्रजीत यादव : प्रश्न यह है कि क्या अमरीका और इंगलैंड ने उन नक्शों को दुरुस्त कर लिया है, जिन में काश्मीर को हमारे देश का भाग न दिखा कर ग़लत ढंग से दिखाया गया है । स्वतंत्र पार्टी के लोग चेकोस्लोवाकिया के दुबचेक की फ़ोटो की पूजा करते हैं, वे उस की एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजा करते हैं, वे उस के "ज़िन्दाबाद" के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि उस के आदर्शवाद को स्थापित करना चाहिए। लेकिन दुबचेक के ज़माने में ही चेकोस्लोवाकिया के नक्शों में हमारे देश के कुछ भाग को ग़लत ढंग से दिखाया गया था ।

आज इस प्रश्न को छेड़ने के पीछे कोरी राजनीति है । क्यों इस राजनीति को उठाया गया है ? पिछले साल, दो साल से देश एक नई दिशा की ओर जा रहा है, देश में एक नई भावना पैदा हो रही है । प्रगति के उस कदम का विरोध करने की स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ एक बड़ी भारी योजना है और यह उस योजना का एक अंश है ।

श्री हरि कृष्ण : मेरा पायंट आफ़ आर्डर है । रूस ने जो ग़लत नक्शे छापे हैं, माननीय सदस्य अगर उस को प्रगति कहते हैं, तो यह एक बहुत अजीब बात है।

श्री चंद्रजीत यादव : माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आप बैठिए, हम को अपनी बात कहने दीजिए। ..... (**व्यवधान**) ....

सभापति महोदय: ऐसे तो हाउस नहीं चल सकता । अगर इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा । इसलिए आप मेहरबानी कर के चलने दीजिए ।

श्री अब्दुल गनी डार : आप तो बड़े बजुर्ग हो, आप क्यों खफा हो जाते हो ? आप सभापति हो और हमारे नेता हो... (**व्यवधान**)......

شری عبدالغنی ڈار : آپ بڑے بزرگ ھو - آپ کیوں خفا ھو جاتے ھو - آپ سبھاپتی ھو اور ھمارے نیتا ھو (ویوڈ ان)

सभापति महोदय : जितनी मर्जी आप लोग बोलना चाहेंगे हम टाइम देंगे । लेकिन जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन को बोलने दो ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा था कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है देश की प्रतिक्रियावादी ताकतों की तरफ से कि हिन्दुस्तान में जो प्रगति के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है या जिन देशों से हमारी दोस्ती है और जिन की दोस्ती को हम कायम रखना चाहते हैं इसलिए कि उस में हमारे भी राष्ट्र का हित है और उन का भी हित है, दुनिया के सारे देशों के साथ दुश्मनी कर के, दुनिया के सारे देशों को दुश्मन के खेमे में रख कर हम अपने को अलगाव की स्थिति में, आइसोलेशन की स्थिति में नहीं रखना चाहते, अगर उन के तर्क को मान लिया जाय तो इस का अर्थ क्या होगा ? ..... (**व्यवधान**)..... .. स्थिति यह है कि आज हम इस बात को स्वीकार करने को यार नहीं हैं......

(**व्यवधान**):....हम यह जानते हैं कि रूस हमारा एक मित्र देश है । रूस की और हमारी मित्रता कुछ आदर्शों के ऊपर, कुछ बुनियादों के ऊपर कायम है। उस मित्रता को हम बनाए रखना चाहते हैं आज भी और भविष्य में भी । लेकिन वह मित्रता अपने देश के सम्मान की कीमत पर, वह मित्रता अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर, वह मित्रता अपने देश की आजादी और सार्वभौमिकता की कीमत के ऊपर चाहे वह रूस के साथ हो, अमेरिका के साभ हो या किसी के साथ भी हो, हम नहीं रखना चाहते । लेकिन प्रश्न यह है कि आप क्या चाहते हैं हम से ? हम ने प्रोटस्ट नोट भेजें । हम ने बातचीत कर के लगातार उन का ध्यान उस की तरफ खींचा । आज अमेरिका गोवा के ऊपर हमारी प्रभुसत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है । आज भी अमेरिका एक एक गोवा के नागरिक को मानता है कि वह पुर्तगाली नागरिक हैं । तो क्या हम अमेरिका के कहने से गोवा के अपने देश के नागरिकों को पुर्तगाली नागरिक मान लें ? अगर अमेरिका हमारी प्रभुसत्ता को काश्मीर के ऊपर नहीं मानता तो क्या उस के कहने से हम काश्मीर को एक स्वतंत्र देश मान लें ? हम को इस प्रश्न के ऊपर विचार करना है कि दुनिया के दूसरे देश क्या कहते हैं हम उस को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । जैसा हमारे किसी मित्र ने कहा है, "मैं समझता हूं उन्होंने सही कहा है भारत का नक्शा और भारत की भूमि के बारे में भारत की सरकार जिस नक्शे को बनाएगी उस को हम एक अधिकृत नक्शा मानेंगे । क्या अमेरिका उस के बारे में कहता है, क्या अंग्रेज कहता है या क्या सोवियत यूनियन कहता है उस का इस से कोई मतलब नहीं होगा । अगर गलत नक्शे होंगे तो उस के खिलाफ हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, उन का ध्यान उस की तरफ खींचेंगे । लेकिन इस के मानी यह नही हैं कि हम उस भूखण्ड

को छोड़ देंगे और उन के पीछे दास बन कर घूमते और दौड़ते फिरेंगे ।

मगर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन और हिन्दुस्तान की दोस्ती तोड़ने की साजिश जो इस देश में प्रतिक्रियावादी ताकतें मिल कर कर रही हैं हम उस को नहीं होने देंगे । हम उस बात को नहीं भूल सकते कि जब काश्मीर का सवाल आया तो सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर के हमारी मदद की । जब गोवा का सवाल आया तो अमेरिका और इंग्लैंड ने पुर्तगाल की मदद की लेकिन तब सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की । हमारे देश के अंदर उन बुनियादी उद्योगों को और हमारे देश की आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए रूस ने जिस प्रकार का संबंध जोड़ा और हमारी मदद की हम उस संबंध को बनाए रखना चाहते हैं ।

अंत में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह सोवियत रूस के नक्शे का सवाल जो है, इस में जहां तक यह बात है कि उस ने गलत नक्शे दिखाए हैं, उस के ऊपर हम सभी एक साथ हैं जहां तक कि इस का सवाल है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम को हाइएस्ट लेवल पर उस सवाल को उठाना चाहिए और उन से कहना चाहिए कि आप हमारे मित्र हैं, आप इस नक्शे को बदलिए । आप की अपनी सरकार है, उस को बदलवाइए ।

श्री पीलू मोदी : और अगर नहीं किया तो ?

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर नहीं किया तो हम फौज नहीं भेजेंगे । मोदी साहब चाहते हैं कि हम उस के लिए फौजें भेजें तो वह हम नहीं करने वाले हैं । माननीय मोरार जी भाई की तरह से मैं यह भी नहीं कहना चाहता– मोरार जी भाई आज कहते हैं कि अपने राजनैतिक संबंध तोड़ दो । कल तक मोरार जी भाई बठे थे कैबिनेट के अंदर और 56 से मामला चल रहा था तब कभी नहीं कहा कि हम रिजाइन करते हैं इस मामले पर । आज निकले हैं और अब जब इस ग्रैंड एलाएंस का नेता बनने की बात करते हैं तब उन को मातृभूमि का वह भाग नजर आता है । तब उन को सोवियत नक्शा याद आता है और तब इस बात को कहते हैं कि इस नक्शे को ठीक करो नहीं तो हम अपना राजनीतिक संबंध तोड़ते हैं । लेकिन इस बात को मैं अपील कर के कहना चाहता हूं .....

SHRI MORARJI DESAI: I have to contradict the statement made. I would like to correct the wrong statement against me. I have not said that on this count diplomatic relations should be completely broken. I have said, in extreme cases that also can be done. But we have not even broken off with China. How can we break off with them? But you must take some strong diplomatic action. That is what I have said. Why are they hesitating about it?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह जो पूरा वातावरण बनाने की कोशिश की गई, मैं इस बात को मानता हूं कि आज उस नक्शे को हमें ठीक कराना है अगर इस बात के ऊपर सभी एक मत हों तो आएं हम सब मिल कर इस बात को करें । लेकिन उस में यह नहीं हो कि सोवियत एम्बैसी के सामने तो करेंगे प्रदर्शन और अमेरिकन एम्बैसी के सामने आप की हिम्मत नहीं पड़ेगी..... **(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : सब जगह चलो ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इस बात को मानता हूं कि सब मिल कर इस में अपनी एक राय दें और पार्लियामेंट की यह राय जाय कि दुनिया के तमाम देश जिन्होंने हमारे नक्शे को गलत छापा है उन देशों के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

साथ हम को प्रधान मंत्री के स्तर पर बात करनी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप एक देश को अलग कर के उस में अपनी राजनीति करना चाहें। यह चीज नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारे का सारा एक राजनैतिक सवाल है, एक साजिश के मातहत है और यह उस साजिश का एक अंग है जिस में हमारी प्रगतिशील अंदरूनी नीतियों का भी विरोध हुआ है और हमारी वाह्य नीतियों का भी विरोध हो रहा है। इसीलिए गृह नीति और विदेश नीति दोनों को जोड़ कर यह ताकतें उस के ऊपर विरोध करना चाहती हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को सदन को मंजूर नहीं करना चाहिए।

श्री **प्रकाशवीर शास्त्री** (हापुड़) : सभापति जी, सत्तारूढ़ दल के और विरोधी पक्ष के भी मैं अपने उन मित्रों को राय से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे देश की एक इंच धरती को भी चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या ब्रिटेन हो, चैकोस्लोवाकिया हो, स्विटजरलैंड हो, कोई भी क्यों न हो, वह किसी दूसरे देश के नक्शे में दिखाता है तो हम को सब को समान स्तर पर रख कर सब का विरोध करना है। क्योंकि यह हमारे देश की रक्षा का प्रश्न है, हमारे देश के स्वाभिमान का प्रश्न है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अमेरिका ने कुछ नक्शों में काश्मीर की धरती को पाकिस्तान का भाग दिखाया या इंग्लैंड ने हमारी धरती को पाकिस्तान का भाग दिखाया, मैं अपने मित्र चन्द्रजीत यादव को याद दिलाना चाहता हूं कि तीसरी संसद के अधिवेशन में शायद हमी थे जिन्होंने इसी संसद के अंदर इस प्रश्न को उठाया था और उस समय अमेरिका की भी निन्दा की थी और ब्रिटेन की भी निंदा की थी।

आज यह प्रश्न आया है कि रूस ने हमारी कुछ धरती को चीन का हिस्सा दिखाया है। मैं इस बात में अपने इन दोस्तों से सहमत हूं कि भारत के पड़ोस में जितने देश हैं, हम को अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए कि उन के साथ हमारी मित्रता न छूटे, हमारी मित्रता बनी रहे। लेकिन हम उस मित्रता की कीमत अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के रूप में नहीं दे सकते, मित्रता की कीमत अपने राष्ट्र की धरती के रूप में नहीं दे सकते। हम उस मित्रता की कीमत अपने देश के किसी भाग को किसी दूसरे देश का हिस्सा दिखाने के रूप में नहीं दे सकते। जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक सोवियत रूस का सवाल है हमारा यह सौभाग्य था कि जिस समय श्री बुल्गानिन और खुश्चेव यहां आए तो उन्होंने यह कहा था कि अगर कभी हिन्दुस्तान के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच आए तो हिमालय के ऊपर खड़े हो कर आवाज लगा देना, हम तुम्हारी सहायता के लिए यहां उपस्थित मिलेंगे। लेकिन चीन ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया और उन से पूछा कि आप ने हमें आश्वासन दिया था तो उन की ओर से यह भी उत्तर आया, शायद चन्द्रजीत जी को भी याद होगा कि भाई के खून में और दोस्त के खून में अन्तर होता है। भाई और दोस्त में भाई का खून ज्यादा गाढ़ा होता है, दोस्त का खून इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है—यह उत्तर भी उन्हीं की ओर से आया था।

दूसरे—जब से यह चीनी नकशे का प्रश्न आया है, इस पर आप भी निन्दा करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस का कुछ समय से बड़ा विरोधी रवैया इस प्रकार बढ़ता जा रहा है कि आज राष्ट्रीय स्वाभिमान से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, दोनों को समान रूप से उसकी निन्दा करनी चाहिये। आप बताइये—जब श्री खुश्चेव यहां पर आये थे, उन्होंने यह कहा था कि काश्मीर की एक-

एक इंच धरती भारत की है, उस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं अब अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं —क्या आज रूस की नीति वही है जो खुश्चेव के समय में थी. . . .

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिलकुल वही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अगर वही है, जैसा कि श्री रामावतार शास्त्री कह रहे हैं, तो जिस समय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ताशकन्द समझौते में शामिल होने के लिये गये थे और यहां यह कह कर गये थे कि काश्मीर के प्रश्न पर वहां किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, क्या श्री कोसिगिन की तरफ से और रूस की सरकार की तरफ से उन पर दबाव नहीं डाला गया था कि समझौते में काश्मीर के प्रश्न को भी शामिल कर लिया जाय। रामावतार शास्त्री जी बताये—क्या उनकी ओर से इस प्रकार का दबाव नहीं डाला गया था ?

सभापति महोदय, अब से कुछ समय पहले जब सरदार स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री थे, हम ने उन से एक प्रश्न पूछा था—क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान को रूस से टैंक मिले हैं, तब सरकार ने इसी संसद में जवाब दिया कि नहीं हम को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब बताइये—उस समय आपकी सूचना सही थी या सदस्यों की सूचना सही थी ? आज उसी प्रकार के हथियार जो रूस भारत को दे रहा है, वे पाकिस्तान को भी दे रहा है–इसमें सच्चाई है या नहीं ?

तीसरी सब से बड़ी बात—आज रूस हमारा मित्र है और हम भी चाहते हैं कि उस के साथ हमारी मित्रता रहनी चाहिये। लेकिन जिस रूस ने ताशकन्द का समझौता कराया, आज जब उसी समझौते को दूसरा पक्ष दियासलाई लगा कर जलाता है, तो क्या रूस की तरफ से उस के विरुद्ध एक शब्द भी कहा गया है कि पाकिस्तान को ताशकन्द समझौते का आदर करना चाहिये, सम्मान करना चाहिये। जब कि भारत उस का पूरा सम्मान कर रहा है। सच्चाई यह है, सभापति महोदय, भारत सरकार नहं कहा जा सकता किन कारणों से पिछले कुछ समय से रूस से भयभीत हो गई है और उसके दबाव में आ कर कुछ इस प्रकार के निर्णय ले रही है जो देश के स्वाभिमान को आगे चल कर मिट्टी में मिलायेंगे। उदाहरण के लिये मैं एक सनसनीखेज बात बतलाना चाहता हूं, जिस को मैंने गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में प्रधान मंत्री के सामने भी कहा था और वह यह कि जब आप समझते हैं कि आज काश्मीर के सम्बध में रूस की नीति बदल गई है, जब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का काश्मीर में संघर्ष होकर चुका है तो मैं पूछना चाहता हूं—इस सरकार ने काश्मीर के फौरेस्ट्स का सर्वे करने के लिये रूस के एक्सपर्ट्स को बुलाया है या नहीं ? यानी काश्मीर के फौरेस्ट्स का सर्वे करने के लिये रशियन एक्सपर्ट्स आये और उस हिस्से का सर्वे कराया गया जो रूस और हिन्दुस्तान की सीमा से मिले हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या हिन्दुस्तान में इस प्रकार के विशेषज्ञों का अभाव हो गया है, जो रूस से इस प्रकार के विशेषज्ञ बुलाये गये और कहा गया कि काश्मीर के जंगलों में जाओ और वहां जा कर यह काम करो।

दूसरी बात, नकशों को लेकर आज हमारे दिलों में जो दर्द और आपत्ति है, वह इसलिये भी है कि एक दफा पहले भी रूस के नक्शे हम को इसी प्रकार अपमानित कर चुके हैं—कोलम्बो प्रस्तावों के समय। उस समय भी रूस के छपे हुए नक्शे प्रमाण के रूप में वहां प्रस्तुत किये गये थे और अक्साई चीन की रेखा जो उस समय खींची गई थी, वह भी रूसी नकशों को सामने रख कर खींची गई थी। तो हम को सब से बड़ी आपत्ति यह है कि कल जिन रूसी नकशों में छपे हुए भारत के मान चित्रों के कारण हम अपमानित हो चुके हैं, वही अपमान हम को दोबारा न देखना पड़े।

सभापति महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा कि हमारी नीति बड़ी संतुलित होनी चाहिये।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

अगर हमारे देश का गलत चित्र, धुंधला चित्र प्रस्तुत करने पर बी० बी० सी० के प्रतिनिधि को निकाला जा सकता है, तो रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस, मास्को रेडियो से प्रतिदिन जो भारत विरोधी समाचार प्रसारित होते हैं, भारत सरकार उन के सम्बन्ध में अपने मुंह पर पट्टी बांध कर क्यों बैठ जाती है यह जो असन्तुलन है इसको किस प्रकार से सन्तुलन कहा जा सकता है ?

सभापति महोदय, इस बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, पीछे जैसे मेरे कानों में आ कर समाचार पड़े हैं कि रूस आज हमारी घरेलू नीतियों में भी हस्तक्षेप करने लगा है। ऐसे समाचार यहां जगह जगह सुनने को मिलते हैं। जैसे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का जब देहावसान हुआ तो रूस से सुझाव आये कि अब राष्ट्रपति किस को चुना जाय। हमारे देश में कमाण्डर-इन-चीफ का निर्वाचन होना है तो बाहर से सुझाव आ रहे हैं कि सेना का थल-सेनापति किस को बनाया जाय। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहे हैं तो बाहर से सुझाव आ रहे हैं कि उस पुरानी परम्परा को समाप्त कर के बाहर से किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाय। इस प्रकार की स्थिति सही है—मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर इस में कुछ भी सत्यांश है तो इस प्रकार का हस्तक्षेप एक तरह से हमारी स्वतन्त्रता को रूस के पास गिरवी रखना होगा। इस सरकार ने जो सब से बड़ी कर्तव्य पालन में चूक की, वह यह कि वह कहते तो यह हैं कि हम ने कर्तव्य पालन किया रूसी नकशों पर प्रतिबन्ध लगाया, लेकिन यह प्रतिबन्ध कब लगाया ? जब इस संसद में शोर मचा, जब इस संसद के सदस्यों ने खड़े होकर सरकार को विवश कर दिया, तब सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया। अगर इस सरकार ने पहले ही यह कदम उठा लिया होता तो शायद आज इस प्रकार से सरकार को आलोचना का विषय न बनना पड़ता।

MR. CHAIRMAN: Mr. Piloo Mody.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I want two minutes to explain my amendment.

SHRI PILOO MODY (Godhra): It has been maintained that our friendship with the Soviet Union is increasing. We are happy if it does, But will the hon. Minister kindly explain just one single point? Upto 1967 even though the Soviet maps showed all of NEFA and Aksai Chin as part of China, when they drew the border, they had a note on it which said "This is a disputed border.'. Since 1967 that note has disappeard and the External Affairs Ministry which is aware of this, has been suppressing this fact from the Parliament and the people of India. I want to know. What is the motivation of the Government of India trying to suppress this fact from the Parliament and the people of India? This is a shift in the Soviet policy. After all, they are very thorough people. They do not do these things inadvertently. The shift in the Soviet attitude about our border—what does it represent? What dangers does it represent to this country?

Thank you.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order, Sir. Is it not proper that after SSP, it is the turn of the SSP speaker? I do not know. Sir, this is very unfair on your part to make this discrimination.

MR. CHAIRMAN: Please don't pass these remarks. You are in the habit of passing remarks.

SHRI SAMAR GUHA: *

MR. CHAIRMAN: This will not go on record.

MR. HEM BARUA.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): This debate on cartographic aggression has aroused emotions and passions and passions. But, Sir, I do not

*not recorded.

want emotions and passions to be aroused. I want you to study this matter in the correct perspective. No anti-Russian lobby should function in this country and no anti-Russian campaign should be carried on because of this cartographic aggression and to say that there is an anti-Russian lobby in this country is entirely wrong. Nothing like that. (*Interrptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): Mischievous.

SHRI HEM BARUA: One mistake does not justify another mistake. The mistake of the Russian cartographic aggression does not justify the mistake committed by other nations like America and possibly Britain.

AN HON. MEMBER: And others.

SHRI HEM BARUA: One mistake does not justify another mistake. We have taken action against the BBC. That would not justify that we should not take action against Russian cartographic aggression. Aggression is aggression. Aggression is always a prelude to physical aggression. There is no doubt about it.

I remember when this matter of Chinese aggression was pointed out on the floor of the Hoose, the Prime Minister at that time pooh-poohed this pointing out the fact. But when China attacked us in 1962, everybody was silent.

All those people who pooh-poohed this idea of cartographic aggression by China were silent when the actual Chinese aggression came. I saw with my own eyes in the military barracks of NEFA occupied once by the Chinese who have written on the whole 'If you, Indians, misbehave, we will come back again'. That is what they have written in the army barracks when the Chinese occupied them during their aggression in 1962.

SHRI S. M. BANERJEE: But we have beaten them away in Nathu La.

SHRI HEM BARUA: Mr. Krishna Menon who was the Defence Minister then made a speech in Bombay that defeat in isolated battles do not make a war. But the fact remains that we were defeated in the isolated battles in the hands of China. There is no doubt about it. We were defeated. There are instances of cartographic aggression by the USA and UNO so far as Kashmir is concerned. But then, we have been protesting against that. Have we not? We have protested against that. What is the harm if we protest against this cartographic aggression by the Soviet Russia? Because, I always believe that Soviet Russia must be friendly with this country. But we want friendship on equal terms, on a reciprocal basis, —not on the basis of surveillance. We don't want that type of friendship.

SHRI PILOO BODY: Friendship with honour.

SHRI HEM BARUA: Yes, friendship with honour. You are right. Mr. Piloo Mody is at least right when he said, we want friendship with honour. That is right. We don't want friendship on the basis of surveillance.

Now, this cartographic aggression has agitated the mind of all. There is no doubt about it. I think, it has agitated the minds of the leaders of the Government also, including Mr. Surendra Pal Singh ji. I think, Sir, is has agitated the mind of everybody.

But, at the same time, this is also a fact that Soviet Russia had given arms and ammunitions to Pakistan. Their argument is this, that they want to wean away Pakistan from the clutches of China. And now the Russian leaders are coming to realise this very fact.

Now, why are we concerned by this cartographic aggression by Soviet Russia? Because of the fact, there was cartographic aggression by China and that was followed by physical action and therefore we are afraid, because of this,

[Shri Hem Barua]

At the same time the question arises What should we do now? There are some people who say that we should go to war with Soviet Russia. I do not think so. We must not go to war with Soviet Russia because we are not in a position to do it firstly. And, secondly, Sir, that would violate the principle of peace.

Sir, we want peace with every country and friendship with every country on equal terms. We do not want to go to war with Soviet Russia because of these facts. But, at the same time, we can do one thing.

We can carry on a map warfare against Soviet Russia. If Soviet Russia refuses to revise these maps, we can do one thing. We can print maps showing Russian territory as Afghan Rumanian Hungarian or even Chinese territory and bombared the Russian Embassy in Delhi with those maps. We can publish such maps showing portions of Russian territory as belonging to Afghanistan, Rumania. Hungary or even China. *Interruption*). We can do that. We can carry on that map warfare. We should do something to make the Russian leaders realise that India cannot be taken for granted. Sir, the trouble is that they think that India is taken for granted.

You know, upto 1967, what happened? The international border in NEFA was taken as a disputed territory by the Russians, and the Russian Ilyushin test pilot refused to fly over there, because that was a disputed territory before 1967. After 1967 that position was also reversed. Now the territory in both Aksai Chin and NEFA are shown as belonging to China and that is what is shown in the maps.

Now, this is a fact that for the first time our Government protested to Soviet Russia in 1956, I think. And that protest was followed by three protests and the latest was in 1969.

Now, Sir, we should take up this matter very boldly about these erroneous maps in the great Soviet Encyclopaedia and see that Soviet Russia publishes the maps correctly.

Thank you.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, अब 6 बजने वाले हैं। आप इसको 6 बजे खत्म कर दीजिए क्योंकि वही नकशा है और वही बात सभी को कहनी हैं।

सभापति महोदय : हम चाहते हैं कि खत्म हो जाये लेकिन अभी पार्टीज के दो तीन लोग बोलने वाले हैं और दो तीन मेम्बर आपकी तरफ से बोलने वाले हैं इसलिए मुश्किल हो जाता है। सदस्यों से मेरा इतना निवेदन जरूर है कि दो-दो मिनट में भी अपनी बात कह लें। .... (**व्यवधान**) ....

श्री मोहन प्रसाद : इस चर्चा का उत्तर या तो आप आज ही मन्त्री महोदय से दिलवा दे या फिर कल तक के लिए इस सेशन को और बढ़ा दिया जाये। .... (**व्यवधान**) ....

श्री रामचरण : मेरा भी यही निवदन है क्योंकि अभी शड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट पर भी डिस्कशन पूरा नही हुआ है। ... (**व्यवधान**) ....

सभापति महोदय : हाउस को बढ़ाने की जहां तक बात है उसके लिए आप स्पीकर साहब को लिखकर दीजिए। .... (**व्यवधान**) .. कृपालानी जी।

श्री राम चरण : इस वक्त तो स्पीकर आप ही हैं।

सभापति महोदय : नहीं, आप उन्ही को लिखकर दीजिए। इस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। .... (**व्यवधान**) .... कृपालानी जी।

श्री मोलहू प्रसाद : शेड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट पर 20 घंटे का डिस्कशन होने की रूलिंग तो यहां पर आपने ही दी थी। . . (**व्यवधान**) . . आप इस सम्बन्ध में हाउस का फैसला ले सकते हैं।

SHRI SAMAR GUHA: We can sit tomorrow also, because the Rajya Sabha is sitting till the 7th.

श्री शिव नारायण : आप मिनिस्टर का जवाब यहां पर दिलवाइये। आपने इस बात का एश्योरस दे रखा है। . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : शिव नारायण जी, आप एक ग्रुप के चीफ व्हिप हैं। अगर आप ही इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। (**व्यवधान**) . . . कृपालानी जी।

श्री राम चरण : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शेड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट अभी तक पोस्टपोन होती चली आई है उसको कन्क्लूड होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो सरकार सबसे पहले उसका उत्तर दे और अगर अभी उत्तर नहीं देना चाहती है तो फिर इस हाउस को एक्सटेंड कर देना चाहिए। . . . (**व्यवधान**) . . . हरिजनों के साथ इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, जब पहले हमने इस हाउस को तीन तारीख के लिए एक्सटेंड किया था तब यह नहीं सोचा था कि इतना काम बाकी रह जायगा। शेड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट पर जो डिस्कशन था वह भी अभी बाकी है। तो मेरा कहना यह है कि जब राज्य सभा सात तारीख तक के लिए बैठ सकती है तो एक दिन के लिए हम भी बढ़ा सकते हैं। आप चेयरमैन हैं, आप पूरे सदन से कह सकते हैं और सदन आपको इस बात की ताकत दे सकता है।

श्री समर गुहा : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री श्रीचन्द गोयल : सभापति के वही अधिकार हैं जो कि अध्यक्ष के होते हैं। (**व्यवधान**) . . . .

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): I can also speak as loud as other people, if they will not allow me to speak. The Chair has called me ten times, but these people are interfering. Other Members have no right to interfere when I have been called.

SHRI UMANATH: If he has got the right to speak, then we have also got the right to raise our voice.

SHRI J. B. KRIPALANI: They are not raising any point of order, but only a point of disorder. Ten times the Chair has called my name, and ten times these people have interfered. And for what? For that which the Chairman says is not within his power; and yet they tell him that it is within his power. Is this the way of doing things? I have been sitting here for five hours. and the Chairman has no mercy upon me; I am an old man, after all, and he will call me only at this time and not earlier. I have to sit here to speak last because some leaders or two or three members get up and shout.

What has been the whole discussion about? These members have only been flinging epithets against each other. I say: plague to both your houses, whether this side or that. The real question is quite different. You accuse this side that they are the friends of America. They accuse you that you are the friends of Russia and China. There are people here who are friends of both China and Russia. Where is an Indian here, I ask?

AN HON. MEMBER: I am an Indian.

SHRI J. B. KRIPALANI: You are . . . (*Interruptions*).

[Shri J. B. Kripalani]

This question of maps is not something new. It has not come to us all of a sudden. We have come across these maps from 1949. When the Chinese invaded Tibet and annexed that territory to China, at that time Sardar Vallabhbhai Patel wrote a letter to Jawaharlal drawing his attention—the letter is there for anybody to see—to the intentions of China, that they will aggress against India, and asking him to be careful. He was not careful.

When Jawaharlal came with the treaty with China in 1954 in this House, I said: 'Sir, did you talk of the maps?' He said "Yes, I mentioned about the maps and Chou-En-lai, said 'these are old maps of the Chiang Kai-shek time; we had no time to look into them'."

I said, "even when there are written treaties there is always the question of interpretation. You have nothing in writing. It is Chou-En-lai's word against your word, one word against another." Even when there are talks between representatives of two nations, afterwards those talks are written down and submitted to the parties concerned to confirm these were right or wrong. Even then there are disputes.

I raised this question at that time. This is not a new question. Why are we afraid of these maps? Because these maps led to aggression on the part of China. It was justified on the basis of these maps: China had already claimed these territories, so they had a right to those territories and these maps were cited in support.

Then you know what happened when there was Chinese aggression—members have mentioned it here; I do not want to repeat it. Russia was a great friend of ours. But at the time they said: 'There is a question of brother; there is a question of a friend'. They said: 'China is our brother and you are our friend. So you will have your proper place. Do not bother about it'.

This question was raised with Russia I think in 1967 or so. They considered these territories as disputed. They knew that these territories are disputed. Have these facts come out or not? Can the Foreign Minister—I mean the Foreign Affairs Minister; sometimes our Foreign Affairs Ministers are raelly 'foreign' Ministers—tell us about it? Will my learned friend, the Minister of Foreign Affairs, tell be whether these are facts or not, whether they are in his record or not or whether he never heard of them.

Therefore, we are apprehensive of what is being done by Russia today, namely printing those maps not even telling us that it is disputed territory, publishing those maps in their latest authorised Encyclopaedia. Nobody should impute motives to us that we are enemies of Russia. We are only proceeding on what has happened historically. When nation is not historically aware of happenings, then say that nation is doomed. We must learn from history, we must learn from experience.

Russia is our friend, but Russia is supplying arms to Pakistan and also naval help to Pakistan. Remember that the foreign policy of a nation does not change because its home policy has changed.

What is Pakistan going to do with its navy? Is England coming back or is America or China going to attack Pakistan? They have no enemies on the sea side. Their only enemy is India so far as the sea is concerned. About land also that is true. So, why Soviet Russia is giving naval help to Pakistan we have not been able to understand. If we think that Soviet Russia will be against Pakistan, we have not read

European history at all. It is always the effort of Russia to have a port in the tropical waters. In Europe it is the Mediterranian. In Asia it is the Indian Ocean. The way lies through Pakistan. As I am alive today to see the result of the mistakes Jawaharlal committed, I hope I will be alive to see the day when you will be left in the lurch. The Soviet Union will be entirely with Pakistan and you can do what you like, because they want a passage to the Arabian sea and the Indian Ocean.

DR. KARNI SINGHT (Bikaner): The humiliation that has been caused to our country as a result of this Soviet cartographic aggression has had its echoes throughout the country. It is adequately clear to us now that India's policies of non-alignment are really becoming a hoax and every day we are more and more getting tied to the apron strings of the Soviet Union. You know as well as all of us do here that the gradual encroachments on India's territories, regarding which we have raised discussions on the floor of the House for a long time, have given our country shock after shock, but the fact remains that this Government, instead of taking some positive stand, whenever it comes to the Soviet Union, it always has a tendency to soft-pedal.

I would like to read out something from Shri Swaran Singh's speech made in the Rajya Sabha. He said:

> "They had further told the Government that the Soviet Union completely respected India's territorial integrity and that the wrong depiction of boundaries on maps did not in any way affect or reffect the Soviet Government's understanding of and respect for India's frontiers."

Then he goes on to reply in another Rajya Sabha debate in a very powerful and a strong voice which only the Minister of a powerful country like India can do:

> "It had been asked whether the Government had asked the Soviet Union to clarify their position ir writing. The Government had nc done it so far."

18 hrs.

I quite understand that the Government is slightly scared of the Soviet Union. But I do hope that they are letting down our country. He says:

> "When they clarified the position in writing, they would clarify it on the map."

Then he goes on further with very brave words:

> "It was easy to write and also, perhaps it might not be quite comfortable to get a clear 'No'."

If the Government is friendly with the Soviet Union I cannot understand why they should be frightened of getting a 'No'. If our case was strong and Soviet Government also are appreciative of India's stand why should there be any difficulty in the Government taking up this matter expeditiously? If you get on 'No' surely we can strongly represent to the Soviet Union that this is not the way of expressing friendship between two nations. If we become subordinate officers to them we are letting down the country.

What does the Soviet Union think of us? In the foreword to the Great Soviet Encyclopaedia, they say:

> "The current third edition of the Great Soviet Encyclopaedia is pubshed in conformity with the decree of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Countcil of Ministers of the Union of Soviet Republics."

It is absolutely clear from this that the maps have sanction of the Soviet

[Dr. Karni Singh]

Union Government. Therefore you cannot turn round and say that the maps have been prepared by mistake. These maps have been deliberately prepared. They are deliberately prepared to give a corridor to the Chinese through Pakistan to ports. We know perfectly well the Minister designs behind it. We also know that if there was a war between China and India—God forbid—we know perfectly well on which side Soviet Union's sympathy will be. This same Government knowing this weakness is buying its arms from the Soviet Union. Whether it is a question of high power transmitters or a satellite for television or whatever it may be, the question arises whether it should be from the free world or the iron curtain countries. We have to realise that as long as India declares itself to be a democratic country, it is a free country. Whether you like it or not you have absolutely nothing in common with the Soviet Union the day when you become a communist country I can understand that. I should like to give you one more quotation before I finish. It is about the Brezhnev Doctrine.

> "The Brezhnev Doctrine, invented to explain and justify retrospectively the invasion of Czechoslovakia, claims that any country which calls itself 'socialist' can never hope to escape from that net and that any attempt to take back to the path of liberal democracy would justify Soviet Military intervension."

You can under stand perfectly well what is behind the minds of the Soviet people, behind this garb of friendship. We should not be led astray by this friendship because if the time came and this country remained a socialist country in terms of the Soviet Union then we shall never be able to go to the path of liberal democracy. Soviet intervention in India would be justified by Brezhnev doctrine. It is a matter of great regret and shame and I can only hope that the Government will wake up to the fact and realise that only democratic countries have something in common and it is essential for us when we start thinking in terms of non-alignment that we understand by non-alignment as a result of inherent internal strength and if we do not, then the wisest thing for us is to have alignment with other countries who think as we do and whose political philosophy is the same as ours.

SHRI AHMAD AGA (Baramulla): Sir, before I begin to speak on the subject proper, I want to place on record that in Parliament, to me, an opportunity to speak has been frequently denied. I have to say it, and I want this to go on record. (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN: The Members are called with due reference to their numbers. This remark is not justified.

SHRI AHMAD AGA: I now wish to speak a few words on the subject under discussion, the mistake committed by the Soviet Government with regard to the map of India. There are many other countries who have also made similar mistakes. The United Kingdom has made the mistake. There are other countries like Switzerland and Sweden and others who have made the mistake.

This is a thing which one can hardly dismiss; it need be rectified by protesting or by asking those countries and saying that "you are friendly and let us try to rectify these mistakes."

But the most important point is, and a thing about which I feel concerned is that the United States of America have comletely omitted to show Kashmir as part of India. They have also deleted the word "Jammu";

the name of my State is Jammu and Kashmir. It is not just "Kashmir". This is very important. The UN and USIS have put down Kashmir as a separate State. I read sometime ago—I do not remember perhaps very clearly—Mr. Bal Raj Madhok's book, *New Alignments in Kashmir*. In that book, he has stated or recommended or he has wanted or wished that Badarwah and other parts of Jammu should be merged with Himachal Pradesh; and so the Jammu territory also. He completely omits and he completely forgets the valley of Kashmir, in the same way. I find the Americans doing the same thing.

When I look at the geography that has been written and the maps that have been prepared—I am not talking in favour or against America or Russia or in favour or against anybody—I am referring to McGraw Hill's *Illustrated World Geography*,— what do I find? It has been prepared by the University of Cambridge and it has been edited in America in 1960. I cannot believe that the University of Cambridge was or is unaware that Jammu and Kashmir State had acceded to India in 1947. I cannot believe that Americans were ignorant or innocent of the fact that we had acceded to India. It is a very clear intrigue on their part. Why do I say this? It is because of this. Why do they want us to remain a separate country? Obviously, they want to create difficulties because they want some trouble there. The USA had a base at Rawalpindi against Russia. Now that they have lost that base, do they want a base at Kashmir? Or, do they want to convert us into something like Vietnam? What do they want to do with us? I speak with much concern about this, than any one of them on that side could speak, because I am vitally concerned with this matter.

The whole point is that our foreign country has to depend on our naional interests. What is our foreign policy? We became free in 1947. We were an under-developed country. So, the first thing that we wanted was development and for that national integration. What was necessary for that? We wanted secularism. Then for development we wanted peace all around and, therefore, non-alignment. Do we see peace around us? What is happening in Indo-China and west Asia? Who are creating these troubles there? Are those troubles coming up on their own? Truman started trouble in Korea, Johnson in Vietnam and Nixon in Cambodia. American youth are dying along with Vietnamese youth. The private sector in America, the free world which Dr. Karni Singh was praising, are selling the war machinery all right and youth are dying. Americans have no right to be there. Why can't we recognise the Provisional Revolutionary Government? When our Foreign Minister goes to Lusaka, he must raise his voice against all these things, against the Portuguese who are still having colonies in Africa and against aparttreid in South Africa; UK's arms for South Africa, illegal Smith regime, etc. Soviet Union came to our help in the UN by using their veto in regard to Kashmir and Goa. Do these people sitting opposite want us to antagonise Russia for having helped us in all these ways and for arming up against China? We have to understand these things in the correct perspective. We must see that what is necessary for us is peace around. For that, our Foreign Minister has to do a much bigger job than merely asking our Embassies throughout the world to keep on correcting a small line here a dot there or a note of integration in their maps.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Sir, but for two points which were advanced which were quite illogical and strange, I would not have taken the trouble to speak. Mr. Umanath curiously made the point that if the maps are changed, it will adversely affect the interests of China. That was the sum and substance of his argument.

SHRI UMANATH: On a point of order, Sir. He has said that I said in

[Shri Umanath]

my speech that if those maps are changed, it will affect the interests of China. I have not said that. He should not proceed on that basis.

MR. CHAIRMAN: All right. You have denied it. Mr. Bhandare may continue.

SHRI R D. BHANDARE: Mrs. Tarkeshwari Sinha said that because Russia and China are communist countries, the drawing up of Soviet maps is bound to be in favour of China.

We have to take into consideration the actual factual position and the situational change after 1954. There are two centres of the Communist world and these two centres are fighting among themselves.

Shastriji said that when there was aggression by China on India, Russia said that blood was thicker than water. But have we forgotten what is happening on the northern side or in Outer Mongolia? Blood is being shed in between China and Russia. That is happening every day.

In spite of our friendly relations with Russia we have sent a note of protest. In spite of the fact that we are interested in the preservation of regional peace, we have sent a strong protest to Russia for drawing these maps.

Last point and I have done. It is really deplorable that a number of countries adopt political attitudes towards India's borders. This aspect should never be forgotten. Therefore, let me warn all countries, whatever may be the friendly relationship and the aid that we might have got from the world at large or from different countries—I quote Carson by way of warning to these different countries who commit cartographic aggression on our country—

> "No woman is grateful at the cost of her chastity, no person can be grateful at the cost of his honour and no country can be grateful at the cost of her independence."

Therefore I am warning all the countries, be careful while dealing with India.

With these words I oppose the proposition which is nothing but a political stunt.

श्री रघुवीर सिंह (रोहतक): चेयरमैन महोदय, यह हमारे देश की खुददारी का सवाल है । यह बड़ा गम्भीर मामला है । ये नक्शे काग़ज़ के टुकड़े नहीं हैं । यह हिन्दुस्तान की इज्जत, हमारी खुददारी, हमारी सालमियत और हमारे इतिहाद का सवाल है । इस को मामूली बात नहीं समझा जाना चाहिए । मैं रूस का बेहद एडमायरर ही नहीं, बल्कि अहसानमन्द भी रहा हूं । वह आदमी आदमी नहीं है, जो अच्छा काम करने वाले का एहसान न माने । मैं एहसानफ़रामोश नहीं हूं । लेकिन अगर रूस के बीस सालों के एहसान का मतलब यह है कि वह हमारी चालीस हज़ार मुरब्बा मील ज़मीन को चीन का दिखा दे, तो मैं कतई एहसान नहीं मानता , मैं सारी बातों को भूल जाता हूं । अगर हिन्दुस्तान का कोई आदमी, या बाहर का कोई देश, हिन्दुस्तान की एक इंच ज़मीन की तरफ़ भी टेढ़ी आंख कर के देख ले, तो हम उसको अपना दोस्त नहीं समझेंगे ।

ये सिर्फ़ हमारे ही ख़यालात नहीं हैं बल्कि आज की डिबेट हमारे पचास करोड़ इन्सानों के जज़बात, सात, एहसात, खुददारी का मुज्जसमा पेश करती है, यहां पर अक्स खींचती है । हिन्दुस्तान कोई मामूली देश नहीं है । वह ग़रीब की औरत नहीं है कि सब उस को भाभी कह कर पुकारें । वह तगड़ा और बहादुर देश है, जिस की शानदार परम्परायें हैं । हमारे नौजवान किसी भी ख़तरे से मुल्क की हिफ़ाज़त करने के लिये तैयार हैं । वे चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कट गये ।

आज भी हम अपने देश की सालमियत, यूनिटी, सोविरेन्टी और इन्ट्रेग्रिटी को बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि मादरे-वतन का एक एक चप्पा हमें अज़ीज है । और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं आप की मार्फत यह कहना चाहता हूं कि न इसजपालियामेंट के बल्कि पचास करोड़ इंसानों के जजबात आप रूस तक पहुंचा दें और सिर्फ बातों बातों में बात नहीं बनेगी, मैं मानता हूं इस बात को कि न सिर्फ हमारे जजबात कागजी और दिखावटी नहीं हैं बल्कि मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि खास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाती तौर पर इस मामले को हाइस्ट लेवल पर लें और जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर भी, अगर रूस का प्राइम मिनिस्टर आए तो उन के साथ इस मामले को लें या परसनल तौर पर उन को चिट्ठी लिखें कि पालियामेंट में यह सब के जबात हैं। हम लड़ाई की बात में यकीन नहीं करते और न हम करेंगे । हमें पता है कि रूस हमारा दोस्त है और हमें पता है दूसरे देशों का भी । हम अब किसी कीमत पर भी अपने देश की इज्जत और ग़ैरत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे । इसी मामले में मैं चाहूंगा कि कम से कम एक बार सारे हाउस की तरफ से यह चीज की जाय कि सारा देश इस नक्शे-जात पर अपने गुस्से का इजहार करता है और हम चाहेंगे कि रूस इस को अप्रीशिएट करे और जल्दी से जल्दी जो गलत नक्शा है न सिर्फ उस को करेक्ट करे बल्कि यह महसूस करे कि वह एक गलत काम हुआ है । चीन को खुश करने के लिए हिन्दुस्तान के साथ वह खिलवाड़ नहीं कर सकता । या तो चीन को ही रखे या हिन्दुस्तान को ही रखे । यह नहीं होगा कि हिन्दुस्तान के जज़बात के साथ खिलवाड़ कर के चीन के जो नक्शेजात हैं उस के साथ हिन्दुस्तान का हिस्सा भी रूस उस में मिला दे। हमारे सैकड़ों-हजारों नौजवानों का खून नेफा मे, लद्दाख में जहां भी वहीं है वह बेकार नहीं जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की तो मुखालिफत करता हूं लेकिन मैं यह चाहूंगा कि ... (व्यवधान)... बिलकुल ठीक बात है कि यह रेजोल्यूशन तो है स्टंट लेकिन यह स्पिरिट जरूर जानी चाहिए रूस के पास कि हिन्दुस्तान का एक एक नर और नारी चाहता है कि हमारे साथ सियासी तौर पर बातचीत न की जाय बल्कि हमारे एहसासात को नोट किया जाय और जो गलती की है, उन्होंने उस नक्शे -जात में उस को करैक्ट किया जाय । मैं चाहता हूं कि इतनी बात हमारी पहुंचाई जाय ।

श्री वि० प्र० मंडल : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं देख रहा हूं कि आप समय, पार्टी की जो लिस्ट जाती है उस के मुताबिक देते हैं । लेकिन कुछ ऐसे मेम्बर भी इस सदन में हैं जिन की कोई पार्टी नहीं है। तो उन के साथ डिस-क्रिमिनेशन होता है । न तो भारत का संविधान और न पालियामैंट का रूल्स आफ कांडक्ट ऐंड बिजनेस ही यह कहता है कि पार्टी के अनुसार समय दिया जाय। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इन लोगों को कहिए कि कांस्टीट्यूशन में भी ऐसा अमेंड-मेंट कर दें कि बिना पार्टी का कोई खड़ा नहीं हो सकता नहीं तो बहुत बड़ा डिस्क्रि-मिनेशन और पक्षपात ऐसे मेम्बर के साथ होता है जो बिना पार्टी का है और सब को हरा कर आया है ।

सभापति महोदय : आपने जो चेयर के बारे म या पार्टी के बारे में कहा है यह बिलकुल गलत है । हम ने कई मर्तबा आप को बुलाया है । आप अनअटैच्ड हैं और बराबर आप बोलें हैं, अनअटैच्ड मेम्बर में

[सभापरि कहोदय]

से आचार्य कृपालानी जी को बुलाया गया है: अनअटैच्ड का 8 मिनट टाइम है, दस मिनट वह बोल कर गए हैं। इसलिए आप की पार्टी का अब कोई टाइम नहीं है । अब डा० सुशीला नायर के बाद हम मिनिस्टर को बुलायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : मडल जी को हम लोगों के टाइम में से दो मिनट दे दिया जाय ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : सभापति महोदय, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ यह देख कर कि हमारे चन्द रूलिंग पार्टी के भाइयों ने यह कोशिश की कि इस चर्चा को एक पार्टीजन या आइडियालाजिकल रूप वह दें । मैं समझती थी कि यह एक ऐसा मसला है जो देश की सीमाओं का मसला है, जो हमारे देश की प्रतिष्ठा का मसला है । इस में सभी पार्टीयों की बराबर भावना होनी चाहिए । । हमारे कुछ भाइयों ने तो इस को प्रगति का सवाल बना दिया । हमारे देश की सीमा रूस-चीन की बताएं इस में प्रगति का सवाल कहां आता है यह मेरी समझ में नहीं आता । किसी ने कह दिया कि यह पुराना सवाल है । अरे, भाई, पुराना सवाल हो या नया सवाल लेकिन सवाल तो यह है कि नया एडीशन जो एन्साइक्लोपीडिया का निकला है उस में हमारी सीमाऐं गलत बताई हैं और रूस जिस को हम मित्र कहते हैं उस ने गलत बताई है । हमें इसलिए खास परेशानी होती है कि हमारे साथ पहले बीत चुकी है । चीन ने पहले इसी प्रकार से गलत सीमाएं बताई थीं और हम से कहा था कि यह पुराने नक्शे हैं हम ठीक कर लेंगे । लेकिन बाद में उस ने ठीक नहीं किया, इतना ही नहीं, हमारी सरहदों पर लड़ाई की । हमारे जवानों का उसमें खून बहा, उन सीमाओं की रक्षा करने में उनकी जानें गईं और आज नौ साल के बाद फिर वही चीज दोबारा होती है । आगे क्या होगा इस का हम को बहुत खतरा है । मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि आज यह सूरत है कि हम यहां कहते हैं कि काश्मीर के नक्शे की बात क्यों नहीं करते? गोवा की बात क्यों नहीं करते ? एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया की बात क्यों नहीं करते ? यानी रूस ने जो गलत नक्शे बनाये, उन की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, हमने हरएक की जिस ने हमारी सीमा गलत बताई उसकी चर्चा और निन्दा की है और हम करने के लिये तैयार हैं। आप ने वह सवाल उठाया हो और हम ने आप का साथ न दिया हो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं । आज अगर एक जनसंघ का भाई सीमाओं का सवाल उठाता है तो चूंकि जनसघ का भाई उठाता है उस से जो चीज गलत है वह सही तो नहीं हो जाएगी, या सही चीज गलत तो नहीं हो जाएगी । मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि सदन में हम ने खड़े हो कर एक प्रस्ताव किया था कि एक एक इंच भूमि अपनी वापस लेंगे । लेकिन भूमि ली नहीं, इतना ही नहीं उस की बात कहना भी हम भूल गए । क्यों रूस को यह हिम्मत हुई नक्शा गलत बनाने की ? क्योंकि इतने दिन से हम कुछ ढीले पड़ गये हैं, कुछ बात नहीं करते, कुछ चर्चा नहीं करते । काश्मीर में भी जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है इतना बड़ा हिस्सा है उस को वापस लेने की हम बात ही नहीं करते । कर्ण सिंह अपने पिता या दादा की कल बात बता रहे थे। लेकिन हम लोग जब काश्मीर गए थे तो उन्होनें एक नक्शा अपने घर में रखा हुआ दिखाया था और बोले थे कि मेरे बड़ों ने 86 लाख वर्ग मील भूमि आप को दी थी । आप की सरकार ने इतने सालों में उस में से आधी से ज्यादा खो दी है कुछ चीन को कुछ पाकिस्तान को । तो सवाल यह आता है कि जब हम चुप हो कर बैठ जाते

हैं, हम अपनी खोई हुई भूमि की बात ही नहीं करते, कुछ चर्चा ही नहीं करते, तो दूसरों को होता है कि हम काहे के लिए इन की लड़ाई लड़ें। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, वाली बात हो जाती है। आज मुद्दई सुस्त हो गया है, यह हमारी शिकायत है। क्यों नहीं चर्चाएं कराई गईं, क्यों नहीं प्रोटेस्ट्स हुए, क्यों नहीं पब्लिक मीटिंग्स कराई गईं ? हम जानते हैं कि मिलिटरिली हम इस सवाल को हल नहीं करने जा रहे हैं। हम शांति के साथ इस सवाल को हल करना चाहते हैं। लेकिन वह तब होगा जब एक जबर्दस्त पब्लिक ओपिनियन हम चारों तरफ मोबिलाइज करें। वह हम ने नही किया। और नहीं किया इतना ही नहीं, हमारा डिप्लोमेटिक प्रयास बिलकुल निल हैं। हम ने लोगों को अपनी सही बात बताई ही नहीं। क्या वजह थी ? क्यों हम लोगों ने सेक्रेटरी जनरल यू० थांट के पास अपनी बात रखी ? . . . (**व्यवधान**) . . . . मैं यह अर्ज़ कर रही थी कि आखिर आप को यह सोचना है कि सेक्रेटरी जनरल यू० थांट के पास यह सारी चीज आप भेज सकते थे इस दरख्वास्त के साथ कि सभी राज्यों को यह हकीकत भेज दी जाये। यह किया जा सकता था। लेकिन आप ने नहीं किया। कच्छ के मामले के वक्त में एक इटरनेशनल कोर्ट में हम गये थे। हेग में एक इन्टरनेलशनल कोर्ट है, हम उस कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन हम वहां भी नहीं गए। हम चुप बठे हैं। हम ने दो तीन खत लिख दिए और फिर सोते रहे। दो तीन खत तो लोग भूल जाते हैं। मगर यह मसला तो आप का है। तकलीफ आप को है, जूता आप के पांव में लग रहा है तो आप को अपना केस पेश करना चाहिए, सारे वक्त सही हकीकत कहना चाहिये और इस प्रश्न के ऊपर सौ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह होता है कि यह करें कैसे ? इन की अपनी कोई नीति नहीं है। मैं आप से कहना चाहती हूं कि डिप्लोमेट्स का बचाव करने के लिए एक भाई ने जो कहा सो ठीक है। डिप्लोमेट्स क्या करेंगे ? जो सरकार की नीति होगी वही तो वह कह सकेंगे ? लेकिन इन की कोई नीति ही नहीं है। इन में हिम्मत नहीं है कि यह अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खुल कर कुछ कह सकें। 58 हजार वर्ग मील हमारे देश का चला जाना यह कोई छोटी बात नहीं है और कहते हैं कि जिस के कब्जे में चीज होती है कानून में भी बहुत कुछ हक उसी का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब उस जमीन पर हमारा कब्जा नहीं रहा है, हमारा आक्यूपेशन नही है, तो जब तक हम सारे वक्त इस सवाल को जिन्दा नहीं रखेंगे, सब के सामने नहीं रखेंगे, कोई चीज होने वाली नहीं है। हम सरकार की इस कमजोर नीति की बहुत जोर से निन्दा करते हैं और हम चाहते हैं कि अभी भी यह आज जाये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जाग जाए और सारी दुनिया में तहलका मचाये कि ये नक्शे गलत बने हैं, इन को विदड्रा करने से काम नहीं चलेगा, इन की दुरुस्ती करवाना चाहिये, आज रूस को गलत नक्शे छापने के लिए हिन्दुस्तान से माफी मांगनी चाहिये।

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुरा): सभापतिजी, बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके ह और शायद कहने के लिये अब कुछ कम ही बचा हो, लेकिन मैं अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि जब कच्छ में पाकिस्तान न हमारी 12 हजार वर्ग मील भूमि पर दखल कर लिया, जब चीन ने हमारी हजारों वर्ग मील भूमि पर दखल कर लिया, उस पर इस सरकार न प्रोटेस्ट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, उस सरकार से आप क्या आशा कर सकते हैं, उस सरकार को भला इस की क्या फिक्र हो सकती है कि कोई देश अपने नक्शों में हमारे किसी भी भाग को दूसर देश का भाग दिखा दे। इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, इस सरकार में गट्स नहीं हैं, बियकृय इम्पेंन्ट सरकार है।

[श्री वि० प्र० मण्डल]

इस सरकार से यह उम्मीद करना कि यह रूस जैसे महान शक्तिशाली देश के विरुद्ध अपनी जबान जोर से खोलेगी, ताकत के साथ अपनी जबान हिलायेगी इस सरकार से ऐसी आशा करना बिलकुल व्यर्थ है।

मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि कोई भी सरकार या उन के सपोर्टर यह कहें—आज से नहीं, आज से 15 वर्ष पहले जिस देश के नक्शों में हमारे देश के भाग को चीन का भाग दिखलाया गया था, और जब उन को नोट दिया गया तो उस को डिस्प्यूटेड पार्ट कहा गया बाद में फिर उस नोट को भी हटा दिया गया, ऐसी घटना को हमारे एक्सटर्नल अफेअर्ज मिनिस्टर कहते हैं कि माइनर बात है—इन को मैं क्या कहूं.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : बेशर्म।

श्री वि० प्र० मंडल : चेयरमैन साहब, इन को हिन्दुस्तान से कोई देश भक्ति नहीं है, केवल गद्दी से इन को मुहब्बत है और शायद ये लोग समझते हैं कि रूस को ना खुश करने से इन की गद्दी बरकरार नहीं रह सकेगी। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इन से कोई उम्मीद करना बिलकुल व्यर्थ है। माननीय सदस्य यहां पर अपनी एनर्जी व्यर्थ में वेस्ट कर रह हैं। इस लिये मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जितने भी देशभक्त सदस्य हैं, देश भक्त पार्टियां यहां पर हैं, एक साथ मिल कर इस सरकार को जल्द से गद्दी से उतार द, इसी में श की भलाई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति जी, अभी इस हाउस में तमाम सदस्यों ने कहा ह कि चाहे रूस के बनाये हुए नक्शे हों, चाहे चीन के बनाये हुए नक्शे हों या किसी भी देश के नक्शे हो, किसी भी नक्शे में यदि हिन्दुस्तान की धरती को या उस के किसी भी भाग को चीन या पाकिस्तान या किसी दूसरे देश का दिखाया जाय, मैं समझता हूं कि वह हमारे देश के नक्शों पर आक्रमण है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने इस विचार धारा का समर्थन किया है, वे कृपया मेरे अमेण्डमेन्ट को पढ़े मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं।

"In view of the Government of India's action to ban those USSR maps which show large chunks of Indian territory as part of China, recommends to the Government to ban or suitably black out all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan.".

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव में मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर। मेरे इस संशोधन को दृष्टि में रखते हुए आप कन्डेम कीजिये, अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया है, तब तो ठीक है, यदि नहीं लिया है तो आप इन को कन्डेम कीजिये, लेकिन अगर एक्शन लिया है तो वह सिर्फ रशियन मैप के लिये ही नहीं, अमेरीकन मैप या कोई भी मैप हो, जो भी हमारे देश के नक्शे को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस की पूरी मुखालफत होनी चाहिये, क्योंकि हिन्दुस्तान का जो नक्शा है, जो हमारा सरकारी नकशा है, वही हमारा नकशा है, उस को न रूस बनाये, न चीन बनाये, हम हिन्दुस्तान के नक्शे को ही अपना नक्शा कहेंगे।

SHRI PILOO MODY: While I sympathise with what he has said, I would submit that it completely changes the scope of what is being discussed here, not only that, but it completely leaves out all reference to condemnation against the Soviet

Union, and, therefore, I do not think that this is an amendment which can be accepted. (*Interruptions*) I would, therefore, recommend to him to bring a separate resolution along those lines.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): I am glad that there is unanimous expression of views by hon. Members belonging to different parties that India strongly disapproves of the continuance of the depiction of Indian territory wrongly in the Soviet maps. There is unanimity on this issue and I have taken note of it, and it is something. Although there have been different viewpoints expressed in the course of the debate and arguments have also been advanced differently and there have also been political overtones, the central thing that has emerged out of this discussion is the unanimous expression of view by this Parliament through its representatives belonging to different parties that all of us are united that this depiction of India-China border is something which is against our interest, and, therefore, all of us are unanimous in urging . . .

17.38 hrs

(*Mr. Speaker in the Chair*)

SHRI PILOO MODY: In condemning.

SHRI SWARAN SINGH: . . . that it should be rectified. I would like to say that we have to see what the original motion of Shri Kanwar Lal Gupta is. He says in his motion that:

> "That this House disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to USSR Government for showing large chunks of Indian territories as part of China in Russian Encyclopaedia.".

What he is asking this House to do is to record that Government have been inactive and they have not sent protests in writing to the Soviet Government clearly bringing out India's viewpoint. That is the gravemen of the charge, and that is the wording of the actual motion. Apparently, Shri Piloo Mody had not studied it before, and, therefore, it has come as a surprise for him.

SHRI S. K. TAPURIAH: He must have heard us all asking him to condemn it. इन्होंने तो बड़े जोर से कहा था कि "कन्डम" शब्द कहिये, आप सुन नहीं रहे थे।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं क्या करूं, ये मोशन तो आप के साथी अपनी तरफ से लाये हैं।

Although there are several political overtones I shall confine myself to the factual position. This erroneous depiction of India-China boundary is of deep concern to the Government of India. The Government had been taking it up at all levels with the Soviet Government since 1956. Apart from several verbal representations made through diplomatic channels both in Delhi and in Moscow, written representations had also been made to the Soviet Government in 1956, 1958, 1966 and 1968.

AN HON. MEMBER: Were they protest notes? Or else, what were they?

SHRI SWARAN SINGH: Further, during official and ministerial visits, the Government have been urging the Soviet Government to correct these erroneous depictions even as recently as June, 1970. The Soviet Government have also been supplied with Survey of India maps on the scale 1 inch to 70 miles. Thus Government have been utilising in a sustained manner diplomatic and official channels for representing or protesting to the Soviet Government on this question. It would, therefore, be entirely wrong to charge Government with inaction in this matter. This is precisely the wording of the

[Shri Swaran Singh]

Resolution, and in view of this information I am supplying to the hon. House, the very basis on which this Motion rests—he probably thought that we had not conveyed anything in writing—disappears.

SHRI R. K. AMIN: Will he lay it on the Table of the House?

SHRI SWARAN SINGH: I have noted his point and will deal with it.

We are now left with the other political things that have been said, to which also I will give a brief reply.

I would like to add that the Soviet Government in response to our representations, both verbal and written, have assured us that delineation of maps had no political significance and that there should be no doubt about the Soviet Union's respect for India's territorial integrity. They also promised to look further into the matter.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: Does that satisfy him?

SHRI SWARAN SINGH: Government have taken up this question with the Soviet Government again in Moscow as well as with the Soviet embassy in New Delhi and conveyed to them the degree of feeling in Parliament and in the public in this country on the wrong depiction of the Indian border in Soviet maps.

I am mentioning all this to show that the basis on which this motion rests is that we have either been inactive or have not conveyed our views strongly to the Soviet Union in writing. That is absolutely incorrect. Therefore, this Motion should not be accepted on this ground in view of the factual information I have given.

I would like to take this opportunity of giving the history of these various maps. In their depiction of the India-China boundary, Soviet maps and atlases broadly follow the Chinese alignment. However, these maps have been consistently adhering more to the pre-1947, Koumintang alignment than to the alignment indicated in the maps published by People's China in 1953, 1956 and 1962. This also answers one of the questions put by an hon. member opposite. The Russian maps thus show the Chang Chenmo Valley within India whereas the Chinese communist maps show the alignment from Karakoram Pass to Demchowk further west to include more areas of India within China. With this exception, the Soviet maps follow generally the Chinese alignment of the boundary.

I may also bring to the attention of the House that all Soviet maps and atlases show Jammu and Kashmir entirely within India.

This is the factual position with regard to maps. It is a well known historical fact that there was a certain Soviet attitude with regard to the British and with regard to the disputes that at that time existed, before independence, between the British and the Chinese. At that time, they had adopted a particular alignment and they have been repeating that. In those circumstances, obviously we know that historically the Soviet sympathies were always against the British because they had a certain attitude in this region, and it was for this reason that they, at that time, even before our independence, adopted what was a Chinese claim in this respect, and that has been repeated in subsequent maps that they have printed from time to time. But this does not correctly represent the position, and it is for this reason that we have taken up this matter strongly with the Soviet Union, in unmistakable terms, not only verbally but in writing. And this unanimous expression of support for this attitude which has been accepted by the House will be an added

source of strength for us to take up even more vigorously with the Soviet Government, and will enable us to press them to make these corrections which should take note of the position and the strong feeling that this country has in this respect.

A question was put by Mr. Mody and also later by Acharya Kripalaniji whether it is a fact that formerly, before 1967, this was shown as disputed territory. That is not correct. Only in one or two small atlases, in one edition only, there was some dotted line. In all the maps ever since independence they have stuck to the Kuomintong maps in which they had accepted more or less the Chinese alignment both in the Aksaichin area as well as in the NEFA area. In some school atlas on a small scale in one of the maps they had shown it as a broken line, and some cartographers interpret it as disputed territory.

I think some rectification can be made. Even if they may be disinclined to adjudicate, as was pointed out by some hon. Members, between two rival claims, at any rate the factual position must be indicated on all maps. Our grievance and the point of our objection which is valid is that even the actual position on the ground is not depicted in these maps. Whatever may be the legal position, the fact remains that on the NEFA side, right up to the border of what was formerly known as the McMahon Line, we are in actual possession, and this fact is not disputed even by China. Even this fact is not brought out in any of the maps that the Soviets have printed.

SHRI POLOO MODY: What do you mean by saying "formerly known as McMahon Line"? Have you changed its name?

SHRI SWARAN SINGH: It is only a line. The actual border is at the moment where the McMahon Line is.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): It is a very well defined line.

SHRI SWARAN SINGH: Our country has traditionally a well recognised border. Let us not go into those details.

SHRI PILOO MODY: I want to know whether you are conceding the McMahon Line to the Chinese.

SHRI SWARAN SINGH: I cannot take a line which probably my hon. friend Mr. Mody is readily prepared to concede. He should be more careful when he makes such a statement. Particularly in borders we should avoid dialectics and we should stick to the factual position. This is the actual, physical position.

Some hon. Members, for some political reasons, wanted to depict that we are not objecting to this because we are beholden to the Soviet Union. There is no doubt that the Soviet Union has been friendly to us. They have helped us in a variety of ways, in our economic development, in some of the vital basic sectors of our economy, in things like machine making, oil, steel, electric power. The Soviet Union have helped us economically in establishing some of these industries, and it is wrong to say that because they have helped us, we are not objecting. Some hon. Members, particularly my Swatantra friends, are allergic to the public sector. So, anything that strengthens the public sector is a source of great allergy to them. That I cannot help. But let us understand that the vast majority of people in this country want that the public sector should grow, so that whatever addition takes place in development and growth should go to the society and not be available only to friends like Mr. Mody.

SHRI PILOO MODY: You cannot grow on third class technology.

SHRI SWARAN SINGH: I do not know what he meant by third class technology.

SHRI PILOO MODY: Of course, you do not. What do you know about technology.

I feel amazed at the logic of the argument when they say that they were not taking it up strongly with the Soviet Union.

SHRI M. L. SONDHI: Are you prepared to lay on the Table of the House a copy of the Notes Verbale and Aide-memoire? You have not been able to protest.... (*Interruptions*).

SHRI S. S. KOTHARI: Let the Minister produce them for the scrutiny of the Speaker and we shall accept the Speaker's assurance about it.

SHRI P. K. DEO: What is the secret about it? Why not they lay them on the Table?

SHRI M. L. SONDHI: Why don't you support us, Sir? They have never protested protests do not exist; they are a figment of their imagination.

SHRI SWARAN SINGH: Mr. Sondhi wants perhaps to try to change the direction of my reply; I am now replying to the arguments which were advanced on the political and economic front; I am not at present replying to the Jan Sangh Member but to a Swatantra Member who had said that because they had helped us in the economic front, we do not want to take it up strongly with them.

SHRI R. K. AMIN: You have misunderstood it. I asked: why should we allow them to have a grip on our economy.

SHRI SWARAN SINGH: You should hear me patiently as I did when you spoke. Somebody else said that we were not taking it up because the CPI was supporting us and we do not want to annoy the CPI. I do not know whether I should reply to this argument. These maps are with us for the last twenty years. We have already protested about them.

SHRI M. L. SONDHI: You have not protested; I charge you. Where is your protest? You are only referring to Note-verbale and Aide-memoire. Why cannot you lay them on the Table? Let history be the judge whether you misled this House on this occasion.

SHRI SWARAN SINGH: I am not yielding..... (*Interruptions*).

SHRI RANGA: When this matter is raised like this, should they not place on the Table of the House the correspondence on this subject?

SHRI SWARAN SINGH: I have said already that we have taken up this matter with the Soviet Union. I mentioned the years in which we had taken it up with the Soviet Union in writing. I have mentioned the other occasions when we had done so. The point that we have to bear in mind is that this is a matter which has been with us.... (*Interruption*) To link it up with the political situation here or the alignment of votes only means that they are still obsessed by some other feeling. What they lost yesterday on something which they regarded as a prestige issue is still on their minds. So far as our maps are concerned, they are maps published by the Survey of India department. If the Americans or other western countries did not show Jammu and Kashmir correctly we have pointed it out to them. If the Soviet Union do not correct the lines in certain other territories we have also been taking it up with them. But, at the same time, let us be quite clear that our boundaries will have to be defended by us and not by either Americans or the Soviet Union. Our Jawans sitting bravely on those heights will defend all these borders and not these speeches here.

With these words, I oppose the motion which was moved by Shri Kanwar Lal Gupta and I accept the amendment which has been moved by Shri S. M. Banerjee.

SHRI RANGA: We would request the Minister to place as soon as possible on the Table of the House whatever correspondence they have carried on in regard to this particular matter, and especially the *aide memoire* to which they themselves have referred.

SHRI SWARAN SINGH: It has not been the practice to place those copies on the Table of the House.

SHRI PILOO MODY: I defy you to do it.

SHRI SWARAN SINGH: I will not place them on the Table of the House.

SHRI PILOO MODY: If it is not the practice, I defy you to do it. Let the whole world realise it. (*Interruption*).

SHRI RANGA: Sir; they have no right whatever to sit there. Are you also going to keep mum like ourselves?

SHRI PILOO MODY: There is no national security involved.

SHRI P. K. DEO: Sir, I rise on a point of order. My point of order is this. In relation to China, the Government published several White Papers, showing all the correspondence with India and China; they were circulated and placed on the Table of the House. Why is the Minister shirking to place on the Table of the House the *aide memoire* or the protest note or just a friendly letter? We would like to know what it is. He must let us know. (*Interruption*).

MR. SPEAKER: If the Government publishes it, well and good, but I cannot force him to do it.

SHRI RANGA: I think it is the privilege of the Chair, in regard to such vital matters, to give proper direction to the Government.

MR. SPEAKER: I cannot force them to publish them.

SHRI PILOO MODY: You can. (*Interruption*). Let him fabricate one and place it on the Table.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: I cannot force them to lay on the Table all the documents.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा): मैं ने आप से दो प्रश्न पूछने की परमिशन मागी थी। आप उस की परमिशन दें। मंत्री महोदय ने कहा कि अंग्रेजों के वक्त से जो नक्शे बनते आ रहे थे उस समय उन की नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी उन की दोस्ती होने के बाद पिछले बीस सालों में उनकी नीति बदली या नहीं? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अंग्रेजी टेलीविजन ने जो गलत फिल्म बनाई हिन्दुस्तान के बारे में उसके बारे में आपने कोई एक्शन लिया या नहीं। अगर अब तक कोई ऐक्शन नहीं लिया है तो अब क्या करेंगे?

19.00 hrs.

श्री स्वर्ण सिंह: जो पालिसी हमारी आज से कुछ साल पहले थी जब कि वह हमारे साथ थे, वही अब भी है। माननीय सदस्य हम को छोड़ गये हैं लेकिन हमारी पालिसी वही है।

श्री कमलनयन बजाज: हम ने गलती की अगर आप का साथ छोड़ कर, तो अब आप उस की प्रतिष्ठ बचाइये।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): चार घंटे की बहस में बहुत सी बात कही गई है। हमें आशा थी कि मंत्री महोदय उनका स्पष्टीकरण करेंगे। हमने कहा था कि हमारे एम्बेसेडर वहां के मंत्री से जब मिल कर आए तो उन्होंने आपको क्या रिपोर्ट दी। हमने मांग की थी कि आप बताएं कि रूस सरकार के सामन बार बार जब इस चीज को रखा गया तो उसने इसका क्या जबाव दिया? यह भी मांग हुई है कि जो कुछ भी प्रोटस्ट नोट तथा कारसपांडेंस आपकी और वहां की सरकार के बीच हुई है, उसको सभा

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

पटल पर रखा जाए। यह भी मांग की गई थी कि रूस सरकार कारिजैंडम इशू करें, इसके बारे में अगर रूस सरकार को कहा गया है तो उसका क्या रिएक्शन था? यह भी जानना चाहा गया था कि अगर रूस सरकार प्रोटेसट् नोट को नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? मंत्री महोदय बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने करीब करीब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमैंट्स का अनुभव प्राप्त कर लिया है। बहुत घाटों का पानी उन्होंने पिया हुआ है। लेकिन वे मंत्री जो रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ ये एक ऐसे पंखे के समान हैं जो घूमता तो है लेकिन हवा नहीं देता है। मंत्री जी एक घंटा या पौन घंटा बोल गए लेकिन कहा क्या, स्पष्ट मालूम नहीं हुआ। वे लट्टू मिनिस्टर हैं जो घूमते हैं। पौन घंटा बोलने के बाद भी उन्होंने एक सवाल का भी जबाब नहीं दिया है।

SHRI RANDHIR SINGH: It should be expunged. Lattoo is bad. I come from Haryana from where he also comes. I understand its meaning.

श्री कंवर लाल गुप्त: मैं दुबारा चार्ज करता हूं। मेरी सूचना यह है कि सरकार ने आज तक एक भी प्रोटेस्ट नोट नहीं भेजा है। कुछ चिट्ठियां गई हैं और बातचीत हुई थी, कुछ लिख कर तो भेजा है लेकिन प्रोटेस्ट नोट नहीं गया है। बार बार मांग करने के बाद भी सरकार जो कारेसपौंडस है उसको टेबल पर रखना नहीं चाहती है और इसी से मेरी बात सिद्ध हो जाती है। इसके अन्दर और भी बहुत सी बात है और वे सारी अगर बाहर आ गई तो बिल्ली थैले के बाहर आ जाएगी और ये नंगे हो जायेंगे। इस वास्ते मैं दुबारा मांग करता हूं कि व्हाइट पेपर जारी किया जाए और सारी कारेसपौंडस को सभा पटल पर रखा जाए।

जहां तक एमेंडमेंटस का सवाल है श्री श्रीचन्द गोयल की एमेंडमेंट को मंजूर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने यह कहा है कि और भी आगे सरकार कार्रवाई करे।

"and not pursuing the matter to any logical conclusion".

यहां दो बातें कही गई हैं। यहां यह कहा गया है कि अमरीका ने भी ऐसा किया है, इंग्लैंड ने भी किया। मैं कहूंगा कि उन्होंने किया है या रूस ने किया है या किसी और ने किया हो, गलत किया है और यह हमारे देश के सम्मान के विरुद्ध है और हमें अपनी पूरी ताकत के साथ जहां रूस को कंडम करना है, वहां अमरीका और इंग्लैंड आदि को भी उतनी ही ताकत के साथ इस मामले में कंडम करना होगा। हमारी पार्टी ने अमरीका या इंग्लैंड की सरकार ने भारत के साथ ज्यादती की है तो उसका उतना ही विरोध किया है जितना कि आज हम रूस का कर रहे हैं। आखिर इंग्लैंड करता है या रूस करता है या अमरीका ऐसा करता है तो वे क्यों करते हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यह सरकार जिम्मेवार है, इस सरकार की डिप्लोमेसी करीब करीब फेल हो गई है। आपको मालूम ही है कि इजराइल के काउंसल ने यहां कहा था कि सीरिया के अन्दर जो किताब पढ़ाई जाती हैं उन में जो नक्शा है उस में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन चार प्रान्तों को एक मस्लिम स्टेट करके दिखाया गया है। इसका खंडन अभी तक नहीं हुआ है। इस तरह से एक के बाद दूसरा देश अगर गलत नक्शे छाप रहा है तो इस सब की जिम्मेवारी सरकार पर है। अगर इंग्लैंड में ऐसा होता है तो वह और भी बुरा है। यह सब गलत है।

यहां कहा गया है कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने सम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी टेरिटोरियल

इंटेग्रेटी को बरकरार रखने के लिए कोई सख्त कदम उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी दोस्ती बढ़ेगी, कम नहीं होगी । अगर आप अपीजमेंट की पालिसी पर चलेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, घुटने टेकेंगे तो आपकी दोस्ती दोस्ती नहीं हो सकती है, गुलामी या कुछ और हो सकती है।

अब सवाल पैदा होता है कि चाहे अमरीका हो या रूस हो या कोई और देश हो, अगर आप प्रोटेस्ट नोट भेजते हैं और वह उसको नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे ? इसका कोई रास्ता आपने नहीं बताया है । क्या यह इसी तरह से चलता रहेगा ? आप ने कहा है कि आखिर को देश की सीमाओं की रक्षा तो हमारी फौजों ने ही करनी है और हमारे पास अपने नक्शे हैं, बाहर कुछ भी होता रहे । बाहर कुछ भी होता रहे तो आप जो यह कहते हैं कि प्रोटेस्ट नोट आपने भेजा, तो उसे आपने क्यों भेजा । इस वास्ते जूझा कि यह चीज आपको पसन्द नहीं । बाहर जो कुछ हो रहा है हमारे देश के बारे में, उसको हम इगनोर नहीं कर सकते हैं, अपनी आंखें मूंद नहीं सकते हैं । इसके बारे में कुछ और भी सोचना चाहिये । हम रिटैलियेट कर सकते हैं । चीन और रूस का सीमाओं को लेकर झगड़ा है । अगर आप रूसी भाग को चीनी नक्शे में दिखा दें तो देखिये क्या होता है । पता लग जायेगा कि कितना रिटैलियेशन होता है ।

यह दब्बू सरकार है । इस सरकार से कोई आशा नहीं रह गई है । यह सरकार न केवल रूस के मामले में बल्कि चीन के मामले में भी नीचे गिरती जा रही है । इसने पहले कहा था कि बांडुंग कान्फ्रेंस के आधार पर बातचीत हम कर सकते हैं । लेकिन अब इन्होंने उस सिद्धान्त को बदल लिया है । अब कहते हैं कि अगर चीन बात करने को तैयार हो तो हम भी तयार हैं । इस तरह से एक के बाद दूसरी ठोकरें आप खा रहे हैं और देश का अपमान करा रहे हैं । यह निन्दा का प्रस्ताव सदन में पास हो या न हो, लेकिन मेरा यह पक्का विश्वास है कि यह प्रस्ताव जनता के दरबार में जब जायेगा तो जनता हमारे साथ होगी और वहां हमें अवश्य इंसाफ मिलेगा । वहीं अब इसका निर्णय होगा, वहीं इंसाफ होगा ।

MR. SPEAKER: I shall now first put Amendment No. 1 in the name of Shri Shri Chand Goyal to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. SPEAKER: Now, I put Amendment No. 2 in the name of Shri S. M. Banerjee to the vote of the House.

The question is:

"That in the motion,—

for "disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to U.S.S.R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encyclopaedia"

substitute—

"in view of the Government of India's action to ban those U.S.S.R. maps which show large chunks of Indian territory as part of China, recommends to the Government to ban or suitably black out all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan" (2)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, I put the motion, as amended, to the vote of the House. The question is:

"That this House in view of the Government of India's action to ban those U.S.S.R. maps which show large chunks of

Indian territory as part of China, recommends to the Government to ban or suitably black out all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan."

The motion was adopted.

19.12 hrs.

RE: VOTING ON CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—*contd.*

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): Sir, since the beginning of the constitution of the Lok Sabha, at no time during this long history of the Lok Sabha there has been any dispute regarding voting or regarding any impersonation. Once a Member of the House, Mr. Mudgal misused his position as a Member of Parliament and this House took a decision to forfeit his membership.

Here is a grave matter which you can have enquired into. It may be a matter of privilege. You can constitute a committee of the Members of Parliament to go into the matter. On an enquiry, we find that Dr. P. Mandal whose division No. is 50 has been staying away from the House for the last four or five days and was not present in the Lok Sabha yesterday during the voting time and his vote has been found recorded as "Aye" in photo No. 620970/016 in the vote recording machines.

SOME MEMBERS: Shame, shame.

DR. RAM SUBHAG SINGH: In respect of another Member, Shri R. S. P. Singh whose division No. is 51 which is adjacent to that seat, it has been found from the record that although Shri R. S. P. Singh was present, his own vote had been recorded through the teller. This is a very grave matter which should be enquired into.

In the morning, we also raised the matter about the bulletin as well as the corrected chart. This thing is on record. Further, about the correction slips, the tellers had five votes as "Ayes" whose votes had already been recorded. The chart shows the final figure of voting as, Ayes—331; Noes—154. There also, an irregularity has been pointed out by the official record. It is not our record. It is your record. Sir. Therefore, I request you that this matter must be gone into either by a committee of the House or you may straightway refer it to the Privileges Committee. And the final corrected figure may be annuonced to the House.

As you know, Sir, I am not at all interested as to who wins and who loses. But this is a matter which will bring disgrace to this Parliament. Take, for instance, I am sitting here and the Deputy-Speaker is sitting here and I press his butten and cast his vote on the machine or on the chart and get my vote recorded by telling it to the teller. This is something which was unknown to this Parliament. This will bring disgrace to this Parliament. This must be enquired into.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है । कल जो निर्णय हुआ, जिस की आपने घोषणा की, जिस की आज आप ने पुष्टि की, उस को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं । लेकिन संसद में मतदान के बारे में सन्देह पदा हो और इस तरह की घटनाय प्रकाश में आय, इस से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा । यह तो मक्का में कुफ्र करने जसी बात है इस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ।

SHRI RANGA (Srikakulam): *rose—*

MR. SPEAKER: No debate on it please. I would request you—no debate please.

SHRI RANGA: Yesterday, not one—I requested you, Mr. P. K. Deo re-